- 20th Year
- Issue: 99
- 08.08.2026 (SATURDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

एफसीआरए पर अमेरिकी टिप्पणी को भारत ने किया खारिज, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया, हमारी संसद ही लेगी फैसला

नयी दिल्ली ०७/०८ (संवाददाता): भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में आज प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक पर एक अमेरिकी सांसद की टिप्पणी को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट शज़्दों में कहा कि भारत के विधायी मामलों में बाहरी टिप्पणियों का कोई स्थान नहीं है और इस संबंध में निर्णय देश की संसद ही करेगी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने एफसीआरए पर की गई टिप्पणियों को देखा है, लेकिन भारत से जुड़े विधायी विषय पूरी तरह देश के आंतरिक मामले हैं और इन पर निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि केवल भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका सहित कई देश विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपने-अपने कानून लागू करते हैं। साथ ही, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की 5 अगस्त को हुई मीडिया बातचीत के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वह एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मंच पर व्यक्त किसी भी विचार, विशेषकर बांग्लादेश की विधिवत निर्वाचित सरकार के संबंध में की गई टिप्पणियों का भारत सरकार समर्थन नहीं करती। इसके अलावा, पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों तथा नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे पर जायसवाल ने कहा कि यह भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन वहां के शिपिंग मंत्रालयों, समुद्री प्राधिकरणों और स्थानीय

प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नाविकों और भारतीय ध्वज वाले जहाजों को हरसंभव सहायता उपलज़्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से भारतीय मिशनों द्वारा 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन भी चलाई जा रही हैं।

साथ ही भारत ने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने, व्यापारिक गतिविधियों के निर्बाध संचालन तथा नागरिक ढांचे, आम नागरिकों, वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना नहीं बनाने की अपील भी दोहराई। श्रीलंका की यात्रा पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अपने समकक्ष विदेश सचिव से उच्चस्तरीय वार्ताएं कीं। इन बैठकों में विकास सहयोग, वर्तमान परियोजनाओं, चक्रवात दित्वाह के बाद शुरू की गई नई विकास योजनाओं सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय मछुआरों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा, जिस पर भारत ने एक बार फिर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मछुआरों की आजीविका और कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के संबंध में ही प्रभासाक्षी के प्रश्न पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने श्रीलंका से लंबे समय से लंबित प्रांतीय परिषद चुनाव शीघ्र कराने तथा संविधान के तहत तमिल समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई टेलीफोन वार्ता पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है

दोनों नेताओं ने इस साझेदारी और आपसी मित्रता को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर चर्चा की। साथ ही पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी विचार-विमर्श किया गया। सोमालिया और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा सहयोग समझौते पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर करीबी नजर बनाए हुए है।

इसी तरह सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हुए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को लेकर भी जायसवाल ने कहा कि भारत इस विकासक्रम पर निकटता से नजर रख रहा है और आवश्यक होने पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी।

अफ्रीका दिवस के आयोजन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत हर वर्ष अफ्रीका के साथ अपनी एकजुटता, सहयोग और साझेदारी का उत्साहपूर्वक उत्सव मनाता है। इस वर्ष आयोजित समारोह में विदेश मंत्री ने भी भाग लिया, जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। बहरहाल, आइये देखते हैं विदेश मंत्रालय की विस्तृत प्रेस वार्ता के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने और ज़्या बातें कहीं।

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से गूंजेगा वंदे मातरम्

नयी दिल्ली ०७/०८ (संवाददाता): रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त को लाल किले पर %वंदे मातरम% बजाया जाएगा। यह पहली बार होगा जब स्वतंत्रता दिवस के औपचारिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत को एक तय कार्यक्रम के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसे प्रधानमंत्री के भाषण के समापन पर राष्ट्रगान से ठीक पहले गाया या बजाया जाएगा। यह कदम संसद द्वारा %राष्ट्रीय सज़्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026% पारित किए जाने के एक हज़्ते से कुछ ज़्यादा समय बाद उठाया गया है। इस विधेयक के ज़रिए %वंदे मातरम% को भी वही सुरक्षा दी गई है जो 1971 के कानून के तहत राष्ट्रगान को मिलती है। 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश किए गए इस बिल के तहत, राष्ट्रीय गीत गाने से जानबूझकर रोकना या इसे गाते समय किसी सभा में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं; दूसरी बार दोषी पाए जाने पर कम से कम एक साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है। अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतज़ार है। लाल किले के कार्यक्रम का पूरा विवरण अभी जारी नहीं किया गया है।

जेपीएससी-जेएसएससी विवाद पर निशिकांत दुबे का अल्टीमेटम, छात्रों को न्याय नहीं मिला तो मैं भूख हडताल पर बैठूंगा

नयी दिल्ली ०७/०८ (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने चेतावनी दी है कि अगर झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उज़्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान 13 जनवरी तक नहीं किया गया, तो वे भूख हड़ताल करने के लिए पार्टी से मंजूरी मांगेंगे। रांची में प्रदर्शन कर रहे उज़्मीदवारों ने इन आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और देरी को लेकर चिंता जताई है।

संसदीय कामकाज और विरोध-प्रदर्शनों के बीच संतुलन बनाने के बारे में बात करते हुए दुबे ने कहा कि संसद का सत्र 13 तारीख तक चलेगा। अगर तब तक कोई फ़ैसला नहीं लिया जाता है, तो भूख हड़ताल करने के लिए पार्टी की मंजूरी की ज़रूरत होगी। मैंने पार्टी अध्यक्ष

से मंजूरी मांगी है। अगर मुझे मंजूरी मिल जाती है, तो मैं 13 तारीख के बाद भूख हड़ताल पर बैठूंगा। उज़्मीदवार सिस्टम में सुधार, भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनके आंदोलन को काफी राजनीतिक समर्थन मिला है और राज्य सरकार पर दबाव बढ़ा है, साथ ही नेताओं ने विरोध प्रदर्शनों को और तेज करने की चेतावनी भी दी है।

दुबे ने कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (छ्वरूरू) और राष्ट्रीय जनता दल (ऋछ्वष्ठ) की आलोचना करते हुए उन पर आरोप लगाया कि भर्ती में कथित गड़बड़ियों के कारण राज्य के युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। उन्होंने पिछले सात-आठ सालों में हुई नियुक्तियों का पूरा ज़्योरा मांगा और सवाल उठाया कि ज़्या इस दौरान इन पार्टियों के नेताओं के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि सवाल राहुल गांधी के बारे में बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है कि राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि पिछले सात-आठ सालों में कांग्रेस नेताओं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और ऋछ्वष्ठ नेताओं के कितने रिश्तेदारों को नौकरियां मिली हैं।

अभय तिवारी पर लगे आरोपों का ज़िक्र करते हुए, जिन्हें उन्होंने मुज़्य आरोपी बताया, दुबे ने दावा किया कि तिवारी ने माना है कि लोगों से पैसे इकट्ठा किए गए और उन्हें सदस्यों और चेयरमैन के बीच बांटा गया। उन्होंने आगे कहा कि तो, इस मामले में कितना भ्रष्टाचार हुआ है? कितनी माताओं ने अपने गहने बेचे हैं?

भभुआ रोड स्टेशन का नाम बदलने का गृह मंत्रालय से प्रस्ताव नहीं मिला-वैष्णव

नयी दिल्ली ०७/०८ (संवाददाता): रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि बिहार के कैमूर जिले में स्थित भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'मां मुंडेश्वरी धाम'' करने के संबंध में गृह मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भाजपा सांसद शिवेश कुमार के सवाल के लिखित जवाब में रेल मंत्री ने उच्च सदन को यह जानकारी दी। कुमार ने सवाल किया था, '' ज़्या बिहार के कैमूर जिले में स्थित भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल के नाम पर मां मुंडेश्वरी धाम रेलवे स्टेशन करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?'' रेल मंत्री वैष्णव ने इसके जवाब में कहा, ''वर्तमान में, गृह मंत्रालय से भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन के लिए रेल मंत्रालय की टिप्पणियां/विचार मांगने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।''

उन्होंने कहा कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, गृह मंत्रालय भारतीय रेल के किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।यह संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों व सुझावों पर विचार करने के बाद संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर ऐसी मंजूरी देता है। रेल मंत्री ने कहा, ''गृह मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, संबंधित राज्य सरकार रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करती है।

आवाजें एक साथ उठती हैं तभी सरकार झुकती है, राहुल गांधी ने पेपर लीकर पर भाजपा को घेरा

नयी दिल्ली ०७/०८ (संवाददाता): शुक्रवार को प्रयागराज में अपने %छात्रों की गूंज% कार्यक्रम से पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ड्ढछ्वक्क के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तभी झुकती है जब आवाज़ें एक साथ उठती हैं।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि परीक्षा के पेपर लीक होने के खिलाफ़ छात्रों के लगातार विरोध-प्रदर्शनों ने सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए मजबूर किया। गुरुवार को ङ्ग पर एक पोस्ट में, गांधी ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर महीनों तक चले विरोध-प्रदर्शनों के बाद पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का ज़िक्र किया और कहा कि सामूहिक कार्रवाई ने सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया। गांधी ने कहा कि प्रयागराज वह शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा युवा

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहाँ का हर छात्र जानता है कि सिस्टम बेईमान हो गया है। छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है; समस्या उस सिस्टम में है जो उनकी मेहनत की कद्र नहीं करता।

उन्होंने नौकरी के उज़्मीदवारों के सामने आने वाली समस्याओं में पेपर लीक, रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों में लंबी देरी का ज़िक्र किया।

कोटा और देहरादून में छात्रों के साथ अपनी हालिया बातचीत का ज़िक्र करते हुए, गांधी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में भी ऐसी ही शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने वाले छात्रों के खिलाफ़ पुलिस ने कार्रवाई की।

उन्होंने कहा कि आखिरकार, एक मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा। यह सरकार तभी झुकती है जब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने छात्रों को 8 अगस्त को शाम 5 बजे प्रयागराज के चक्क ग्राउंड में होने वाली बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। चक्क कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड के इस्तेमाल की मंजूरी वापस लेने के बाद इस कार्यक्रम पर कुछ समय के लिए अनिश्चितता के बादल छा गए थे। मैनेजमेंट ने इसके लिए पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी वजहों और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया था जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।

झारखंड में १० लाख का इनामी माओवादी सालुका कायम ने किया आत्मसमर्पण

रांची ०७/०८ (संवाददाता): झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कज़्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के जोनल कमेटी सदस्य और सक्रिय दो महिला उग्रवादियों ने शुक्रवार को सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोनल कमेटी सदस्य पर 10 लाख रुपये का इनाम था। अधिकारी ने बताया कि जोनल कमेटी सदस्य की पहचान सालुका कायम के रूप में हुई है जबकि दो महिला उग्रवादियों में से एक कोडोमुनी कोड़ा पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया, ''सारंडा और

कोल्हान के जंगलों में पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियानों के परिणामस्वरूप सालुका कायम ने आत्मसमर्पण किया।'' अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ का रहने वाला कायम भाकपा (माओवादी) के गिरज़्तार पोलित ज़्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के समूह में सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि बेसरा पर दो करोड़ रुपये से अधिक का इनाम घोषित था और वह 175 मामलों में वांछित था। उसे पिछले महीने के अंत में गिरज़्तार किया गया था। अधिकारी ने बताया कि कायम कई वर्षों से माओवादी संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था और उसके खिलाफ सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी विस्फोट करने, हत्या, रंगदारी और सरकारी संपज़ि को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप हैं।

पीएम मोदी ने बागी टीएमसी सांसदों से कहा, वे क्या कहते है, इसकी चिंता न करें, मैं आपके साथ हूं

नयी दिल्ली ०७/०८ (संवाददाता): शुक्रवार को नई दिल्ली में नाश्ते पर हुई एक खास बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागी सांसदों को भरोसा दिलाया कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खबरों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि आपके बारे में ज़्या कहा जा रहा है, इसकी चिंता न करें। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। यह बैठक मॉनसून सत्र के दौरान संसद में हो रहे नए गठबंधनों के बीच विपक्ष के पूर्व सांसदों का स्वागत करने और उन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (ह्लष्ठ) में शामिल करने के लिए बुलाई गई थी। इस नाश्ते में लगभग 45 सांसद शामिल हुए। इनमें ञ्जरूष्ट के 20 बागी सांसद (जो हाल ही में %नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया%

या ह्लष्टक्क में शामिल हुए हैं), उद्धव सेना के सात पूर्व सांसद (जिनमें से छह आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए), नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP) के 20 सांसद और NCPI (अजित पवार गुट) के दो सांसद शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सांसदों से लोगों के बीच अपनी पहुँच बढ़ाने को कहा और कहा कि देश की तरक्की के लिए राज्य की तरक्की बहुत ज़रूरी है। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार, हर सांसद को उनके सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ाव की जानकारी वाला एक प्रिंटआउट दिया गया और प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के साथ डिजिटल जुड़ाव बढ़ाने को कहा। मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि जब बंगाल तरक्की करता है, तो भारत तरक्की करता है और सांसदों से कहा कि राज्य में अभी बहुत काम करना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास सिर्फ़ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूर्वोज़र राज्यों को भी बेहतर कनेज़्टिविटी और तेज़ी से विकास की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने सांसदों को सालाना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह भी दी और कहा कि आगे के बड़े काम को देखते हुए उन्हें फिट रहने की जरूरत है। चाय के दौरान बैठक में कुछ हल्के-फुल्के पल भी आए। जब ।चा चाय परोसी गई, तो बीजेपी सांसद शताज़्दी रॉय ने प्रधानमंत्री को बताया कि यह ज़्या है और कहा कि यह पश्चिम बंगाल में भी मिलती है। मोदी ने फिर से कहा कि बंगाल को भारत की तरक्की में अपनी अहम भूमिका फिर से हासिल करनी चाहिए; उन्होंने कहा कि जब राज्य ने पहले तरक्की की थी, तो देश ने भी तरक्की की थी। बातचीत के दौरान हंसी-मज़ाक का माहौल तब बना जब सीनियर सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री कई ऐसे नेताओं से घिरे हुए हैं जो पहले एज़्टर थे - इनमें शताज़्दी रॉय, सयोनी घोष, जून मालिया और रचना बनर्जी शामिल हैं। उन्होंने मज़ाक में कहा कि उनके साथ बने रहने के लिए प्रधानमंत्री को भी फिट रहना होगा।NCPI की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि हम उनके ज्ञान और हमारे साथ उनके व्यवहार, दोनों से ही बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने हमें अपनाया और कहा कि हम सब एक परिवार हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हम पश्चिम बंगाल की बड़ी तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे... उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया- कि हम तरक्की और विकास के लिए साथ मिलकर काम करेंगे।

विविध समाचार

जंतर मंतर कनेक्शन बताने वाले अमृतसर पुलिस चीफ का तबादला, आप पर भाजपा हमलावर

नयी दिल्ली ०७/०८ (संवाददाता): आम आदमी पार्टी (क्क) की पंजाब सरकार ने अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को उनके पद से हटा दिया, जिसके बाद उनके तबादले के समय को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भुल्लर ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान समर्थित एक कथित टेरर मॉड्यूल और जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से उसके कथित संबंधों का दावा किया था। पंजाब के गृह विभाग द्वारा 7 अगस्त को जारी एक आदेश के अनुसार, भुल्लर की जगह हरमनबीर सिंह को नियुक्त किया गया है, जो अभी अमृतसर में छ्वद्व बॉर्डर रेंज के तौर पर काम कर रहे हैं।

आदेश के अनुसार, भुल्लर को अगले आदेश तक छ्वक्क ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा। उनकी पोस्टिंग का आदेश बाद में जारी किया जाएगा। यह ट्रांसफर आदेश अमृतसर कमिश्नरेट द्वारा पाकिस्तान समर्थित कथित टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में नौ लोगों (जिनमें चार नाबालिग भी शामिल हैं) की गिरफ़्तारी की घोषणा के कुछ ही समय बाद आया है। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी विदेश में बैठे ढ्ढस्ढ्ढ हैंडलर्स के कहने पर काम कर रहे थे और सुरक्षा ठिकानों की निगरानी कर रहे थे।

4 अगस्त को एक ब्रीफिंग के दौरान, भुल्लर ने बताया कि जांच से पता चला है कि गिरफ़्तार किए गए कुछ आरोपियों ने जंतर-मंतर का दौरा किया था, कथित तौर पर वहां की रेकी की थी और विरोध स्थल पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों को पेट्रोल बम से निशाना बनाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने तीन पिस्तौल, नौ जिंदा कारतूस और चार पेट्रोल बोतल बम बरामद करने की भी घोषणा की थी। बाद में पंजाब सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि भुल्लर ने यह नहीं कहा था कि गिरफ़्तार किए गए लोग जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे या प्रदर्शनकारियों का कथित आतंकी मॉड्यूल से कोई संबंध था।

भुलर को हटाए जाने से अब राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है; पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सवाल उठाया है कि ज़्या पुलिस प्रमुख की टिप्पणियों का इस तबादले से कोई लेना-देना था। बिट्टू ने ङ्ग पर एक पोस्ट में कहा कि गुरप्रीत भुल्लर के ट्रांसफर का समय निश्चित रूप से सवाल खड़े करेगा। ज़्या जंतर-मंतर पर कथित साजिश के बारे में उनके सटीक खुलासों से केजरीवाल परेशान हो गए? बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर कथित साज़िश के बारे में भुल्लर के बयानों से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बेचैनी पैदा हो सकती है।

सौरभ दास ने आवास में यूट्यूबरों के घुसने का लगाया आरोप, दिल्ली पुलिस से मांगी सुरक्षा

नयी दिल्ली ०७/०८ (संवाददाता): कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के मुज़्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बुधवार को आरोप लगाया कि यूट्यूबर और मीडियाकर्मियों के एक समूह ने उनके आवास में घुसकर अंदर की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। इस घटना को अपने परिवार के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा बताते हुए उन्होंने दिल्ली पुलिस से हस्तक्षेप की अपील की है। महाराष्ट्र में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) की दो-दिवसीय बैठक में शामिल होने की बात कहने वाले दास ने एज़्स पर पोस्ट में आरोप लगाया कि बुधवार सुबह 15-20 लोग उनके आवास पर पहुंच गए, जबकि कुछ लोग पिछली रात से ही बाहर डेरा डाले हुए थे।

दास ने कहा, कुछ यूट्यूबर और मीडिया चैनल जबरन मेरे घर में घुस गए और अंदर के दृश्य दिखा रहे हैं। यह न केवल मेरी निजता का हनन है, बल्कि मेरे और मेरे परिवार के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरा भी है। संभावित परिणामों के प्रति आगाह करते हुए दास ने कहा, अगर इसके परिणामस्वरूप कोई असामाजिक तत्व मेरे आवास पर मुझ पर हमला करता है, तो ये यूट्यूबर और उनका तालमेल बिठाने वाले आलोचक (सोशल मीडिया पर सक्रिय) इसके लिए सीधे तौर पर जिज़्मेदार होंगे।

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में दावा किया कि इन वीडियो के कारण असामाजिक तत्व और गुंडे सक्रिय हो गए हैं जिससे घर में रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यह मामला संसद में भी उठा। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उसने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया है। तृणमूल के राज्यसभा नेता डेरेक ओ ब्रायन ने एज़्स पर कार्यवाही का एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि पार्टी ने सांसद राजीव कुमार के माध्यम से सदन में यह मुद्दा उठाया। दास ने ओ ब्रायन के पोस्ट पर जवाब देते हुए इस हस्तक्षेप के लिए उनका आभार व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एज़्स पर दास की पोस्ट को पुनः साझा करते हुए प्रतिक्रिया दी, ''यह मोदी जी का असली चेहरा है।'' कॉजपा ने कथित परीक्षा पत्र लीक मामले को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रभावित छात्रों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना आंदोलन शुरू किया था।

एक महीने से अधिक समय तक चला यह विरोध प्रदर्शन 25 जुलाई को प्रधान के इस्तीफे और प्रदर्शनकारियों की कई मांगों पर केंद्र के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ था। यह संगठन फिलहाल अपनी भावी रणनीति तय करने के लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दो-दिवसीय राष्ट्रीय सज़्मेलन आयोजित कर रहा है।

अतीक अहमद के बेटों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली पेरोल, अबान के जनाजे में होंगे शामिल

प्रयागराज ०७/०८ (संवाददाता): माफिया और पूर्व सांसद दिवंगत अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए उसके दो भाइयों झांसी जेल में बंद अली अहमद और लखनऊ जेल में कैद मोहज़्मद उमर को शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सशर्त पेरोल मिल गई। दोनों के प्रयागराज पहुंचने के बाद शनिवार सुबह शव को कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत ने अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उमर और अहमद को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सशर्त पेरोल दी। अदालत ने निर्देश दिया कि

अंतिम संस्कार और परिवार के चार सदस्यों का मिलन पूरा होने के बाद उमर और अहमद को पुलिस अभिरक्षा में उनकी जेलों में वापस लाया जाएगा। अदालत ने कहा, उमर और अहमद किसी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे, सोशल मीडिया एवं इलेज़्ट्रॉनिक मीडिया समेत मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। अदालत ने कहा, इसके अलावा, वे अंतिम संस्कार कर रहे धार्मिक व्यक्ति, अपनी बुआ परवीन कुरैशी और भाई अहजम अहमद के अलावा किसी से बातचीत नहीं करेंगे। साथ ही वे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के निर्देशों का सज़्ती से पालन करेंगे। झांसी जिले में बृहस्पतिवार को एक सड़क हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गयी थी, जबकि कार सवार तीन अन्य लोग घायल हो गये थे जिन्हें कल रात झांसी के अस्पताल से लाकर प्रयागराज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह अबान का शव हटवा गांव स्थित उनकी बुआ परवीन कुरैशी के घर लाया गया। अबान की कब्र भी अतीक की कब्र के पास तैयार की गई है। इसी कब्रिस्तान में अतीक के भाई अशरफ और बेटे असद की कब्र है।सड़क दुर्घटना का शिकार हुए अबान और उनके एक साथी के शव लेकर देर रात उनके परिजन प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे और शुक्रवार सुबह यहां पहुंचे। झांसी में बृहस्पतिवार की सुबह हुई दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद अतीक के बेटे अजहम और घायलों के परिजन देर शाम झांसी पहुंचे थे। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया।अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसकी तेज रज़्तार एसयूवी कार बेकाबू होने के कारण एक डिवाइडर से टकराकर पलट गयी। इस हादसे में अबान अहमद (21) और उसके दोस्त सोनू (25) की मौत हो गई। इसके अलावा कार सवार आजम, मोहज़्मद जावेद और उमर घायल हुए।अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर पत्रकार बनकर पहुंचे तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के समय पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जा रहे थे।

झारखंड जेपीएससी विरोध: सरकार से बातचीत को तैयार छात्र, विडियो रिकॉर्डिंग की रखी शर्त

रांची ०७/०८ (संवाददाता): रांची में JPSC पेपर लीक को लेकर विरोध कर रहे छात्र झारखंड सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार हो गए हैं और उन्होंने बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की है। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब सैकड़ों छात्र 14वीं छ्वक्स्ष्ट परीक्षा, छ्वस्स्ष्ट-ष्टत्रु और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर अपना विरोध जारी रखे हुए हैं और ष्टक्चढ्ढ जांच तथा भर्ती एजेंसियों में सुधार की मांग कर रहे हैं। इससे पहले दिन में, झारखंड के मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के कथित पेपर लीक का मामला सिर्फ़ राज्य का नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी सरकार छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह बात तब कही जब छात्रों ने अपना विरोध तेज़ कर दिया और राज्य में क्क्स्ष्ट और स्स्ष्ट परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में पाँच और प्रदर्शनकारी शामिल हो गए।

उन्होंने कहा कि युवा साथियों की चिंताएँ सरकार के लिए बेहद गंभीर मामला हैं और कथित पेपर लीक सिर्फ़ झारखंड का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश भर के कई राज्यों के युवाओं के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार इस मामले पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एजेंसियां दिन-रात जांच कर रही हैं और दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। उनका मकसद सिर्फ़ जांच करना नहीं, बल्कि मेरे युवा दोस्तों को पूरी तरह से समाधान देना है।

एक अहम घटनाक्रम में, झारखंड के मुज़्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार के दरवाज़े सभी के लिए हमेशा खुले हैं। कोई भी छात्र या उज़्मीदवार, जिसकी कोई मांग या सुझाव हो, वह राज्य सरकार के सामने अपनी बात रख सकता है। छ्वक्स्ष्ट के विरोध कर रहे छात्रों में से एक ने आरोप लगाया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (छ्वस्स्ष्ट)-ष्टत्रु पेपर लीक की पिछली जांचों से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि हो सकता है कि कुछ महीनों बाद इस ताज़ा जांच को भी दबा दिया जाए।

तेजस्वी यादव ने बिहार डीजीपी से सीवान एसपी पर कार्रवाई मांगी, छात्र प्रदर्शन में एके-४७ इस्तेमाल का मुद्दा उठाया

पटना ०७/०८ (संवाददाता): राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार से मुलाकात की और 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एके-47 राइफल के कथित इस्तेमाल के मामले में सीवान के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों पर इस तरह की राइफल के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। राजद नेता ने पत्रकारों से कहा, ''प्रदर्शनकारियों पर एके-47 का इस्तेमाल केवल मुज़्यमंत्री सम्राट चौधरी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर ही किया जा सकता था। इस मुद्दे पर दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं। संबंधित पुलिस

अधीक्षक (एसपी) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।'' जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ज़्या उन्होंने डीजीपी से संबंधित एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो यादव ने कहा, ''प्रदर्शनकारी छात्रों पर एकके-47 के इस्तेमाल के मामले में एसपी समेत सब पर कार्रवाई होनी चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''मैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाया।'' यादव ने कहा कि वह दोनों नेताओं को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वे यहां आएं और 25 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों से मुलाकात करें। उस दिन वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्यों ने नीट प्रश्नपत्र लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुलाए गए 'बिहार बंद' के समर्थन में कई जिलों में प्रदर्शन किये थे और उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई थी। बंद के दौरान पटना, सारण, सीवान, औरंगाबाद, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया और भोजपुर में हिंसा हुई, जबकि समस्तीपुर, नवादा, नालंदा, मधुबनी और शेखपुरा में मामूली प्रदर्शन देखने को मिले थे। प्रदर्शनकारियों ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था, जिसके बाद कई छात्रों को हिरासत में लिया गया।

ई२० ईंधन विवाद, आप का ऐलान, आठ से देशभर में शुरु होगा राष्ट्रव्यापी अभियान

०७/०८ (संवाददाता): आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह ई20 ईंधन के खिलाफ आठ अगस्त से देशभर में टाउन हॉल (संवाद कार्यक्रम) की श्रृंखला शुरू करेगी।

पार्टी का उद्देश्य वाहन मालिकों से बातचीत करना और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से जुड़ी समस्याओं पर लोगों की राय जानना है। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यहां संवाददाता सज़्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने इससे पहले दिल्ली में इस मुद्दे पर एक टाउन हॉल आयोजित किया था, जिसमें देशभर से करीब सात लाख लोगों ने ऑनलाइन भाग लिया था।

उन्होंने कहा कि अब पार्टी इस अभियान को विभिन्न राज्यों में ले जाएगी और सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से ई20 ईंधन (80 प्रतिशत पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत फसल-आधारित इथेनॉल) को लेकर लोगों की चिंताओं को समझने तथा इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का काम करेगी। सिंह ने कहा कि आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज राष्ट्रव्यापी अभियान का समन्वय करेंगे। पार्टी के अनुसार, यह अभियान आठ अगस्त को पश्चिम बंगाल में शुरू होगा, जिसके बाद नौ अगस्त को गुजरात और हरियाणा, 11 अगस्त को तेलंगाना और 17 अगस्त को छज़्तीसगढ़ में कार्यक्रम होंगे। सिंह ने कहा कि इन सार्वजनिक बैठकों के दौरान पार्टी लोगों से ई20 ईंधन के खिलाफ उसके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी करेगी। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ई20 ईंधन कार्यक्रम का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि इसे लोगों पर थोपा जा रहा है और इससे वाहनों के प्रदर्शन पर असर पड़ता है।

कांग्रेस में शामिल हुए १८ प्रमुख लोग, पूर्व आइएएस, आईपीएस हुए शामिल

नयी दिल्ली ०७/०८ (संवाददाता):पूर्व नौकरशाहों, अधिवक्ताओं तथा विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े 18 लोग बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी ने इसे अपने संगठन के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा, कांग्रेस के उज़्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल जयहिंद तथा लोकसभा सदस्य राकेश राठौर की मौजूदगी में नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया गया। कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता अनूप कुमार आंबेडकर, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता मयंक यादव और श्रेय यादव, उज़्तर प्रदेश के पूर्व पीसीएस अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी चौधरी खुशी राम, उज़्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी बी.पी. अशोक, किसान नेता रोहित जाखड़, केरल के सेवानिवृज़्त पुलिस महानिदेशक सुदेश कुमार, आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी वकार चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल की पूर्व राष्ट्रीय सचिव सावित्री गौतम शामिल हैं।

विविध समाचार

क्या आप भी मानते हैं एसआईपी से जुड़ी ये बातें? निवेश से पहले जान लें वरना डूब सकते हैं पैसे

आज के समय में ज्यादातर लोगों के लिए अपनी बचत को बढ़ाने और भविष्य के लिए पूंजी जमा करने का सबसे फेमस तरीका SIP बन गया है। छोटे इंवेस्ट से शुरुआत करने की सुविधा के कारण करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन, जितनी तेजी से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उतनी ही तेजी से इससे जुड़ी गलतफहमियां यानि मिथक भी फैली हैं। ऐसे में इनके बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि एसआईपी से जुड़े मिथक क्या हैं।

मिथक 1: SIP से तुरंत और हमेशा रिटर्न का मिलना

कई लोगों को लगता है कि एसआईपी शुरू करते ही उनका पैसा रॉकेट की तरह बढ़ने लगेगा। जबकि एसआईपी शेयर बाजार से जुड़ी होती है। ऐसे में बाजार में उतार-चढ़ाव होना आम बात है।

कम समय यानि 1 से 2 साल में आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में भी दिख सकता है। एसआईपी का असली फायदा कंपाउंडिंग से मिलता है, जिसके लिए आपको कम से कम 5 से 10 साल का धैर्य रखना जरूरी है।

मिथक 2: हर टॉप रेटेड या मशहूर फंड में निवेश करना सही

अक्सर लोग स्टार रेटिंग या पिछले साल के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड को देखकर निवेश कर देते हैं। जरूरी नहीं कि जो फंड पिछले साल टॉप पर था, वह आगे भी वैसा ही रहे। निवेश हमेशा अपनी जरूरत, लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता को देखकर करना चाहिए, न कि केवल लोकप्रियता के आधार पर।

मिथक 3: एक बार शुरू करने के बाद SIP कभी बंद न करें

अगर आपके द्वारा चुने गए फंड का प्रदर्शन लगातार 1-2 साल तक अपने बेंचमार्क से खराब चल रहा है या आपके जीवन के लक्ष्य पूरे हो गए हैं, तो एसआईपी को रिव्यू करना और जरूरत पड़ने पर बंद करना या दूसरे फंड में स्विच करना जरूरी होता है।

मिथक 4: बाजार गिरने पर SIP बंद कर देनी चाहिए

बता दें कि यह सबसे खतरनाक मिथक है। जब बाजार गिरता है, तो निवेशक डरकर अपनी किस्तें रोक देते हैं। जबकि, असलियत में, बाजार गिरने पर आपको उतनी ही रकम में ज्यादा 'यूनिट्स' मिलती हैं। बाजार के निचले लेवल पर निवेश चालू रखने से ही पयूचर में बड़ा मुनाफा होता है। गिरावट के समय एसआईपी बंद करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।

मिथक 5: SIP अपने आप मुनाफा दिला देगी, कुछ करने की जरूरत नहीं

एसआईपी कोई जादुई मशीन नहीं है। आपको समय-समय पर अपने निवेश को देखते रहना चाहिए। बाजार की स्थितियों और फंड मैनेजर के फैसलों का असर आपके पैसे पर पड़ता है। ऐसे में नजर रखें।

क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में रखें इन जरूरी बातों का ध्यान

आजकल हर बैंक बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर ठीक तरीके से किया जाए तो इससे ना सिर्फ आपको मुश्किल वक्त से उबरने में मदद मिलती है, साथ ही आपको अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर होने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप पहली बार क्रेडिट कार्ड लेने जा रही है तो इसके इस्तेमाल को लेकर आप एक्साइटेड होंगी।

क्रेडिट कार्ड का यूज करते हुए आपको कई तरह के एक्साइटिंग ऑफर मिलते हैं। आप जितना खर्च करती हैं, उतनी ही तरह के लाभ आप पा सकती हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड जितनी सहूलियत देता है, बेहिसाब खर्च होने पर उतना ही नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अगर आप इसके इस्तेमाल में लापरवाह हुए तो फायदे के बजाय आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए आपको इसका इस्तेमाल करते हुए काफी होशियारी से काम लेना होगा। आइए जानें कि आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ध्यान रखें-

क्रेडिट कार्ड पर लगने वाली फीस की करें तुलना

सभी क्रेडिट कार्ड पर अलग तरह से फीस और इंट्रस्ट रेट लगते हैं और इन पर बेनिफिट भी अलग होते हैं। जिस क्रेडिट कार्ड पर सबसे कम फीस वसूली जा रही हो, सबसे कम इंट्रस्ट देना पड़ता हो और ऐसे बेनिफिट्स मिलें, जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, वही आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है कि अलग-अलग क्रेडिट कार्ड में इस तरह की सुविधाएं मिल रही हों, ऐसे में आप इन कार्ड्स से मिलने वाले ऑफर और उन पर लगने वाली फीस का कंपेरिजन कर लें तो अपने लिए सही विकल्प चुन सकती हैं।

क्रेडिट कार्ड है एक बड़ी जिम्मेदारी

क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है। जरूरत पड़ने पर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे भी उधार ले सकते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर लिमिट खत्म होने या फिर एक निश्चित अवधि के बाद आपको खर्च की गई रकम को वापस करना होता है। अगर इसमें देरी होती है या फिर आप उधार लिए पैसे देने में फेल होती हैं, तो इस पर इंट्रस्ट की दरें काफी ज्यादा होती हैं। इसीलिए क्रेडिट कार्ड से खर्च बहुत ज्यादा जरूरी चीजों पर ही करें और यह सुनिश्चित करें कि तय समय में कार्ड की ईएमआई चुका दी जाए।

बिलिंग साइकिल से पहले चुकाएं बकाया राशि

अगर आप क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले भारी-भरकम लेट चार्जेज से बची रहना चाहती हैं तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप बिलिंग साइकिल की तारीख से पहले ही अपनी बकाया राशि चुका दें। मसलन अगर आपकी बिलिंग साइकिल महीने की 7 तारीख को होती है तो आप 6 तारीख तक अपनी खर्च की हुई रकम वापस कार्ड के खाते में जमा कर दें।

बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें इस्तेमाल

आप सोच रही होंगी कि क्रेडिट कार्ड को सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप कार्ड को नियमित रूप से नहीं इस्तेमाल करेंगी, तो उस पर भी चार्ज लग सकते हैं। ऐसे में आप उससे छोटे-छोटे खर्च करें, जिन्हें आसानी से चुकाया जा सके। इससे आपको अतिरिक्त चार्ज नहीं देने पड़ेंगे।

एक क्रेडिट कार्ड रखने में है समझदारी

जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगी तो आपके पास कई बैंकों से ऑफर आ सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप वो सभी ऑफर स्वीकार कर लें। पहली बार कार्ड लेते हुए एक कार्ड को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने में समझदारी है। अपनी जरूरत के हिसाब से सही क्रेडिट कार्ड लें। ध्यान रखें कि जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड आपके पास होंगे, आप पर कर्ज उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा।

लो क्रेडिट लिमिट वाला कार्ड चुनें

क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हुए नए-नए ऑफर्स का लाभ उठाने में काफी मजा आता है, लेकिन इसी मजे के चक्कर में कई बार खर्च आवश्यकता से ज्यादा हो जाता है। कई बार इस पैसे को बैंक को चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्रेडिट लिमिट आपकी मदद कर सकती है। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट कम है तो आप उस लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं करेंगी और उस राशि को समय रहते चुकाने में भी कामयाब होंगी।

इन 5 जगह पर क्रेडिट कार्ड से करें भुगतान, होगा फायदा

आज के समय में सब कुछ डिजिटल हो गया है। अब ना आपको बैंक में जाने की जरूरत है ना ही हमेशा पर्स उठाकर चलने की। डिजिटल पेमेंट करने के कई फायदे भी होते हैं। कुछ जगह पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर आपको कैशबैक जैसे कई लाभ मिलते हैं। हम आज आपको ऐसी 5 जगहों के बारे में बताएंगे जहां क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर आपको फायदा मिलेगा।

ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त

ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से कई फायदे मिलते हैं। दरअसल आजकल हर प्लेटफार्म पर कार्ड से भुगतान करने पर कुछ प्रतिशत ऑफ मिलता है। वहीं अगर कैश भुगतान करें तो किसी तरह का ऑफ नहीं मिलता। इसके अलावा बहुत बार क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर कैशबैक भी मिलता है। ऐसे में अगर आप भी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें ताकि आप कुछ परसेंट ऑफ और कैशबैक का फायदा उठा सकें।

इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने के लिए

इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते वक्त क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर हमें एक्स्ट्रा प्वाइंट्स मिलते हैं जो क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। बहुत से शोरूम में कार्ड से भुगतान करने पर 5 से 10 प्रतिशत तक का ऑफ भी मिलता है जो आपके टोटल बिल में कटौती कर सकता है। इतना ही नहीं बहुत बार क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है।

ट्रैवल के भुगतान के लिए करें इस्तेमाल

टैक्सी से लेकर एयर टिकट की बुकिंग के लिए भी क्रेडिट कार्ड यूज करना फायदेमंद रहता है। अगर आपके कार्ड के टोटल प्वाइंट ज्यादा है तो आपकी टिकट की कीमत में भी कटौती हो सकती है। एयर टिकट ही नहीं टैक्सी आदि के भुगतान के वक्त भी क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर कुछ परसेंट ऑफ मिलता है। बहुत बार ओला और उबर जैसी कंपनी भी अपने यात्रियों को ऑनलाइन भुगतान करने पर 50 प्रतिशत तक का ऑफ देती है।

मॉल से शॉपिंग करते वक्त

मॉल में अक्सर अलग-अलग क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ना कोई ऑफर चल रहा होता है। कई बार ऐसे भी ऑफर होते हैं कि 5000 का सामान खरीदकर कार्ड से भुगतान करने पर 2000 रुपए की कटौती हो जाती है। ऐसे ऑफर का फायदा उठाने के लिए आप भी मॉल में भुगतान करते वक्त कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

होटल में करें भुगतान

मॉल की तरह होटल में भी कार्ड से भुगतान करने पर ऑफ मिलता है। बहुत बार क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर कैशबैक प्वाइंट भी मिलते हैं। आजकल ज्यादा कैश लेकर चलना सुरक्षित नहीं है। साथ ही क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर कुछ फायदे भी मिलते हैं। इन फायदों को उठाने के लिए आप भी क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं।

बारिश की वजह से दीवारों और सीढ़ियों पर जम गई है गहरी काई? झटपट हटाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

बारिश के मौसम में दीवारों और सीढ़ियों पर काई जम जाती है, जिसे जड़ से हटाना काफी मुश्किल होता है। ये दरअसल, घर की सुंदरता को खराब करता है और यह फिसलन की वजह से दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। ऐसे में, नजरअंदाज करने के बजाय कुछ असरदार और आसान तरीकों से आप इसे झटपट हटा सकते हैं।

बारिश का मौसम दिखने में जितना सुहावना होता है, उतना ही अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आता है। इन्हीं में से एक बड़ी समस्या है- दीवारों, सीढ़ियों और छत की फर्श पर गहरी काई का जमना। यह फिसलन भरी काई बच्चे, बड़े और बूढ़े हर किसी के लिए मुसिबत होते हैं। यह न सिर्फ आपके घर की सुंदरता को प्रभावित करती है, बल्कि इस पर पैर पड़ने से गंभीर चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। अगर आप भी बारिश की वजह से इस जिद्दी काई से परेशान हैं और इसे हटाने का कोई आसान व कारगर तरीका ढूंढ रही हैं, तो अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपको ऐसे तीन असरदार घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप इस काई को मिनटों में साफ कर सकती हैं। ये तरीके सस्ते और बेहद प्रभावी भी हैं। इनके इस्तेमाल से आपकी दीवारों और फर्श को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इस आर्टिकल में दिए गए 3 असरदार तरीकों को अपनाकर आप इसे आसानी से और झटपट हटा सकते हैं।

सख्त ब्रश और खुरचने वाले औजार

एक सख्त ब्रश या खुरचने वाले औजार से रगड़कर काई को हटाने की कोशिश करें। अगर फिर भी ये नहीं हट रहे हैं, तो इन जगहों पर नमक और पानी का घोल डालें और इसे मोटे पेपर से रब करें। आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से खुरचने के लिए बालू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यह रखेपन से जल्दी छूटेगा और आपकी बालकनी, सीढ़ियां और दीवारें भी काई से मुक्त हो जाएंगे। काई हटाने के बाद, भविष्य में इसे फिर से जमने से रोकने के लिए उस जगह को पूरी तरह सूखने दें। अगर संभव हो तो उस जगह पर पानी जमा न होने दें और सूरज की रोशनी पड़ने दें।

ब्लीच और पानी का घोल

काई हटाने का यह सबसे प्रभावी और सस्ता तरीका है। ब्लीच में मौजूद रसायन काई और फफूंदी को जड़ से खत्म कर देते हैं। एक बाल्टी में 1 भाग ब्लीच और 3 भाग पानी मिलाएं। इस घोल को सीधे काई वाली जगह पर स्प्रे करें या ब्रश की मदद से लगाएं। इसे 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। एक सख्त ब्रश से रगड़कर साफ करें और फिर पानी से धो लें। ब्लीच का इस्तेमाल करते समय दस्ताने जरूर पहनें।

बेकिंग सोडा, सिरका और पानी का घोल

अगर आप ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो सिरका एक प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प है। सिरके में मौजूद एसिड काई को ढीला कर देता है। एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा, सफेद सिरका और पानी मिलाएं। घोल को काई वाली सतह पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। इसे 30 मिनट से 1 घंटे तक लगा रहने दें। फिर एक सख्त ब्रश से रगड़कर साफ करें और पानी से धो लें।

कलिंग समाचार

शनिवार 08 अगस्त 2026

आंदोलन के बाद अगला कदम या जश्न

कॉकरोच जनता पार्टी की पहल पर जंतर–मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन शुरु हुआ, जिसमें स्वतस्फूर्त लोग जुड़ते गए। कॉकरोच जनता पार्टी की पहल पर जंतर–मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन शुरु हुआ, जिसमें स्वतस्फूर्त लोग जुड़ते गए। सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता इस आंदोलन का अहम चेहरा बन गए, क्योंकि उन्होंने छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए अनशन किया। कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी के दो प्रमुख प्रवक्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के आधिकारिक एक्स एकाउंट पर सोनम वांगचुक की ही तस्वीर इन पंक्तियों के लिखे जाने तक लगी हुई है। अब धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन खत्म हो गया है, सोनम वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, तो राजघाट पर प्रणाम कर वे लद्दाख जा चुके हैं। अनशन तो उन्होंने प्रधान के इस्तीफे से पहले ही खत्म कर दिया था, वो भी केन्द्रीय मंत्री के हाथ से जूस पीकर और भगवा पटका ओढ़कर। इधर जंतर–मंतर पर साफ–सफाई भी हो चुकी है। लिहाजा पिछले सवा महीने से धरने के मंच पर बैठे सीजेपी के लोगों को भी फुर्सत मिल गई है। शायद प्रधान के इस्तीफे की खुशी में या शायद आंदोलन की थकान उतारने के लिए इन लोगों ने एक पार्टी की, जिसकी तस्वीरों और वीडियो पर अब सवाल उठ रहे हैं, जो लाजिमी भी हैं। दिल्ली में कथित तौर पर किसी पांच सितारा होटल में सौरव दास, आशुतोष रांका समेत सीजेपी के कई लोगों के नाचते–गाते वीडियो आए हैं। ये पार्टी बिल्कुल वैसी ही है, जैसी नयी पीढ़ी यानी जेन ज़ी की होती है। डीजे पर एक के बाद एक बजते पार्टी सांग्स और उस पर थिरकते युवा। नए साल या जन्मदिन अथवा किसी और मौके पर आज के बच्चे ऐसे ही जश्न मनाते हैं। लेकिन इनकी मुहिम क्या यहीं तक थी। ध्यान रहे कि धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा अब तक सरकार ने इनकी बाकी मांगों पर केवल आश्वासन ही दिया है, उन पर अमल नहीं हुआ है। पेपर लीक के कारण जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों के लिए पहले एक करोड़ के मुआवजे की मांग थी, जो सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाएगा में बदल दी गई। ये भी कहा गया था कि आंदोलन के कारण जिन लोगों पर मामले दर्ज हुए हैं, वो वापस किए जाएंगे। लेकिन क्या सरकार के कहने को ही पर्याप्त माना जाए। क्योंकि सरकार ने तो यह भी कहा था कि पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक अदालत बैठी भी, लेकिन सीबीआई के वकील पहुंचे नहीं तो अब ये सुनवाई 3 अगस्त तक टाल दी गई है। क्या फास्ट ट्रैक अदालतें ऐसे ही चलेंगी। सीबीआई भी सरकार से बाहर तो नहीं है, ऐसे में सवाल तो उठेगा ही सीबीआई ने फास्ट ट्रैक को अहमियत क्यों नहीं दी। क्यों उसके वकीलों ने तय तारीख पर उपस्थित होना जरुरी नहीं समझा। इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रैंड्स कहते हुए एक और रील बना दी, इस बार खड़े होकर इंस्टाग्राम पर संदेश दिया है कि नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में छह सदस्यों वाली उच्च अधिकार समिति बनाई गई है, जो परीक्षा में सुधार पर काम करेगी और इसमें तकनीकी के सर्वोत्कृष्ट उपयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। इन्हीं श्रीमान नीलेकणि ने यूपीए सरकार में आधार कार्ड की अवधारणा पर काम किया था, तब भाजपा को इस पर घोर आपत्ति थी। बहरहाल, ये उच्चाधिकार समिति चाहे जितने सुधारों की सिफारिश कर ले और अच्छी से अच्छी तकनीक से परीक्षाएं करवाने के सुझाव दे, लेकिन जिन लोगों को इस पर असल में काम करना है, उसे व्यवहार में उतारना है, क्या वे सब एकदम से सौ प्रतिशत ईमानदार हो जाएंगे। फास्ट ट्रैक अदालत का पहला हश्र देखकर ही यह आशंका उठ रही है। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन केवल जंतर–मंतर तक सीमित नहीं था, देश के बाकी शहरों में भी यह उतनी ही तीव्रता के साथ खड़ा हुआ। बिहार में भी दिल्ली की तरह पुलिस की दमनकारी नीति सामने आई। बल्कि सीवान में अभिषेक पटेल नाम के पुलिसकर्मी ने एके 47 जैसे हथियार से आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, इसका वीडियो सामने आया है। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस पर आवाज उठाई तो अभिषेक पटेल को निलंबित किया गया है।

भारत–रूस संबंधों में नया रणनीतिगत बदलाव

के रवींद्रन शिखर

स मेलन में होने वाली चर्चाओं में बड़ी आर्थिक संभावनाओं पर भी बात होने की संभावना है, भले ही रक्षा और ऊर्जा सुर्खियों में छाए रहें। दोनों देशों के बीच व्यापार के आंकड़ों में पहले वृद्धि में तेज़ी दिखी, फिर कुछ समय के लिए ठहराव भी आया, जो लगातार बढ़ोतरी को अनलॉक करने के लिए ढांचागत दखल की ज़रूरत को दिखाता है। राजनीतिक इरादे और आर्थिक व्यावहारिक सोच का बढ़ता मेल भारत–रूस रिश्ते को नई र .तार दे रहा है, जिससे नई दिल्ली में होने वाला शिखर स मेलन एक ऐसी भागीदारी में एक अहम पल बन रहा है जिसने पहले ही दशकों के भूराजनीतिक बदलावों को झेला है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा, जिसे %स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप% (विशेष और तरजीही भागीदारी) की शब्दावली में बताया गया है, दोनों तरफ़ से एक ऐसे एजेंडा को आगे बढ़ाने की इच्छा का संकेत देता है जो अब पहले की रुकावटों तक सीमित नहीं है और अब सिर्फ पुरानी मजबूरियों से बना नहीं है।

जबकि पिछले साल ज़्यादातर बातचीत में तेल ही हावी रहा,वैश्विक ऊर्जा बाजार में हो रहे बदलाव और वाशिंगटन में चल रही बातचीत ने हाइड्रोकार्बन को लेकर दबाव कम कर दिया है, जिससे नई दिल्ली और मॉस्को अपना ध्यान रक्षा सहयोग और बड़े रणनीतिगत संबंधों पर केन्द्रित कर पा रहे हैं। इस बदलाव को मुमकिन बनाने वाला एक बड़ा बदलाव क्रूड सप्लाई को लेकर उ मीदों का पुनर्समायोजन है। वैश्विक तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव और भारत की ऊर्जा टोकरी की बदलती बनावट ने ऐसा माहौल बना दिया है, जहां रूसी हेवी क्रूड बनाम अमेरिकी लाइट क्रूड को लेकर टकराव अब ज़रूरी नहीं रहा। भारत की कई अन्य आपूर्तिकर्ताओं से आयात संतुलित करने की क्षमता, और खरीदे जाने वाले तेल के ग्रेड के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा की कमी ने, वाशिंगटन और मॉस्को के साथ उसकी भागीदारी के बीच टकराव की गुंजाइश कम कर दी है। बदले में, इसने भारत के राजनयिक बैंडविड्थ से एक बड़ा बोझ कम कर दिया है, जिससे नीति योजनाकार रूस के साथ सहयोग के पुराने तरीकों पर फिर से विचार कर सकते हैं और किसी दूसरे भागीदार को नाराज़ करने की चिंता किए बिना नए तरीके खोज सकते हैं।

इस बदलाव से बनी जगह खास तौर पर रक्षा सहयोग में साफ़ दिखती है, जो लंबे समय से भारत–रूस समीकरण का सबसे अहम हिस्सा रहा है। दोनों सरकारों ने माना है कि रक्षा संबंधों को गहरा करना दिल्ली शिखर स मेलन का केन्द्र होगा। उ मीद है कि चर्चा पारंपरिक खरीदार–बिक्रीकर्ता गत्यात्मकता से आगे बढ़ेगी, जिसने शीतयुद्ध काल के बाद से सैन्य संबंधों को आकार दिया है। भारत, जो अब रक्षा उत्पान में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए अपनी कोशिशों में ज़्यादा ज़ोर दे रहा है, ऐसे मॉडल खोज रहा है जिनमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त विनिर्माण और साइबर क्षमताओं, स्पेस आधारित संपदा और एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम जैसे उभरते हुए क्षेत्र में लंबे समय तक सहयोग शामिल हो।

मॉस्को, अपनी तरफ से, भारत को एक भरोसेमंद भागीदार के तौर पर बनाए रखने में फ़ायदा देखता है, ऐसे समय में जब उसके अपने रणनीतिगत माहौल पर काफ़ी दबाव पड़ा है। पश्चिमी पाबंदियों और बदलते क्षेत्रीय गठबंधनों ने रूस को अपने आर्थिक और राजनीतिक जुड़ावों में विविधता लाने के लिए मजबूर किया है। भारत का बड़ा बाज़ार, इसका बढ़ता रक्षा औद्योगिक आधार और इसका भूराजनीतिक वजन रूस को स्थिरता और मौका दोनों देते हैं। आने वाला शिखर स मेलन इन मेलजोल को मज़बूत करने का एक रास्ता देता है, मौजूदा संबंधों और उत्पादनों पर काम करते हुए भविष्य के ऐसे रास्ते बताता है जो साझा रणनीतिगत गणना को दिखाते हैं।

इन बातों का नई दिल्ली की विदेश नीति के लिए भी बड़े असर हैं। रणनीतिगत स्वायत्तता पर भारत का लंबे समय से ज़ोर, बदलते वैश्विक शक्ति ढांचा द्वारा लगातार जांचा जा रहा है। अमेरिका–चीन तनाव के बदलते हालात, अन्तरराष्ट्रीय प्रणाली में रूस की बदलती स्थिति और पश्चिम एशिया को आकार दे रही अनिश्चितताओं ने भारत की राजनयिक फुर्ती पर नई मांगें खड़ी कर दी हैं। इस माहौल में, रूस के साथ एक मजबूत भागीदारी बनाए रखने से कई मकसद पूरे होते हैं– यह भारत की पैंतरेबाज़ी की आज़ादी बनाए रखने में मदद करता है, इसके रक्षा प्रदर्शन में विविधता पक्का करता है और दूसरी बड़ी ताकतों के साथ बातचीत में फ़ायदा देता है। इनमें से कई गणनाओं के साथ ऊर्जा सुरक्षा जुड़ी हुई है। भारत की विविधिकरण रणनीति का मतलब है कि कोई भी एक देश इसके आपूर्ति स्रोत पर हावी नहीं है, लेकिन रूस एक अहम भूमिका निभाता रहा है।

इसका हेवी क्रूड भारत के रिफाइनिंग इकोसिस्टम में सटीक बैठता है, जबकि अमेरिकी लाइट क्रूड लोच और माप की अधिकता देता है। जैसे–जैसे वैश्विक बाजार ओपेक के व्यवहार में बदलाव, गैर–ओपेक आपूर्ति के विस्तार और कमोडिटी के बहाव को प्रभावित करने वाली बड़ी अस्थिरता के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, भारत के आयात प्रोफ़ाइल में रूसी और अमेरिकी क्रूड के बीच टकराव की कमी दोनों भागीदार के साथ समानांतर स बंध कायम रखने के लिए जगह देती है। इसने न केवल भूराजनीतिक जोखिमों को कम किया है, बल्कि भारत की ऊर्जा राजनयिकता को आगे बढ़ाने की क्षमता को भी गहरा किया है जो व्यावहारिक और लचीली दोनों है। शिखर स मेलन में होने वाली चर्चाओं में बड़ी आर्थिक संभावनाओं पर भी बात होने की संभावना है, भले ही रक्षा और ऊर्जा सुर्खियों में छाए रहें। दोनों देशों के बीच व्यापार के आंकड़ों में पहले वृद्धि में तेज़ी दिखी, फिर कुछ समय के लिए ठहराव भी आया, जो लगातार बढ़ोतरी को अनलॉक करने के लिए ढांचागत दखल की ज़रूरत को दिखाता है। कनेक्टिविटी की दिक्कतें, निर्यात की टोकरी में सीमित विविधता और नियामक अवरोधों ने पारंपरिक रूप से तरक्की में रुकावट डाली है। मौजूदा माहौल में, जहां सप्लाई चेन की जोखिमों को कम कर उसे बेहतर बनाना वैश्विक प्राथमिकता बन गयी है, भारत और रूस द्विपक्षीय व्यापार को स्थिर करने के तरीके खोज सकते हैं। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, खनिज संसाधन और नाभिकीय प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाना शामिल हो सकता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहले से ही स पूरक चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा, जिस भूराजनीतिक पृष्ठभूमि में यह शिखर स मेलन हो रहा है, वह दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रकृति तय कर रहा है।

भारत की पश्चिमी भागीदारी और रूस के साथ अपनी पार परिक दोस्ती के बीच लगातार संतुलन बनाना एक बारीक काम है। नई दिल्ली ने बड़ी ताकतों के ध्रुवीकरण में फंसने से बचने के बजाय, अपने रणनीतिगत हितों को आगे बढ़ाने के लिए कई कर्ताधर्ताओं के साथ अपने रिश्तों का फायदा उठाया है। वॉशिंगटन में तेल से जुड़े तनाव में कमी ने इस संतुलन के काम में आत्मतोष की एक परत को कम कर दिया है। इससे भारत मॉस्को के साथ शिखर स मेलन में ज़्यादा आत्मबल के साथ जा सकता है, यह जानते हुए कि वह दूसरे भागीदारों के साथ रिश्तों में तनाव डाले बिना अपने संबंधों को बचा सकता है। रूस भी भारत के बढ़ते प्रोफाइल मूल्य को पहचानता है। बहुपक्षीय मंचों में इसकी भूमिका, इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था और इसकी बढ़ती रक्षा क्षमता, ये सभी मॉस्को की रणनीतिगत गणना में हिस्सा लेते हैं। यह शिखर स मेलन क्रेमलिन को लंबे समय से चली आ रही अच्छी नीयत को और मज़बूत करने का मौका देता है, साथ ही दूसरे वैश्विक कर्ताधर्ताओं को यह सिग्नल भी देता है कि रूस अपने आस–पड़ोस के अलावा भी भागीदारी में आगे है। मॉस्को के लिए, भारत के साथ मज़बूत रिश्ते बनाए रखना किसी एक भागीदार पर बहुत ज़्यादा निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने का भी एक तरीका है। रिश्ते का महत्वपूर्ण कारक पहलू है —भरोसा, विश्वसनीयता और राजनीतिक सुविधा, जो शिखर स मेलन के आस–पास की र .तार को बनाए रखने वाला एक मज़बूतकारक बना हुआ है। वैश्विक ढांचे में बदलाव और अमेरिका तथा यूरोप के साथ भारत के करीबी जुड़ाव के बावजूद, नई दिल्ली और मॉस्को के बीच भागीदारी की ऐतिहासिक भावना खत्म नहीं हुई है। शिखर स मेलन के लिए अपनाई गई शब्दावली, जिसमें %स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप (विशेष और तरजीही भागीदारी) पर ज़ोर दिया गया है, सिर्फ र स्मी नहीं है। यह दशकों के सहयोग से बने रिश्ते को दिखाता है, एक ऐसा रिश्ता जिसे दोनों देश उन वजहों से महत्व देते हैं जो पारंपरिक संबंधों को रणनीतिगत तार्किकता के साथ मिलाती हैं।

मोबाइल का साथी या आस्तीन का सांप

सर्वमित्रा सुरजन

दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की डिजिटल जासूसी के खिलाफ कड़े कानून हैं, लेकिन यहां तो मांझी ही नाव डुबोने वाले बने हुए हैं। वैसे इस फैसले पर अब बड़ी फोन निर्माता कंपनियां भी सहमत नहीं हैं। ऐप्पल अपने स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप प्रीलोड करने के आदेश का पालन करने की योजना नहीं बना रहा है। खबर है कि वह अपनी चिंताओं से भारत सरकार को अवगत कराएगा। मोदी सरकार तानाशाही कायम करने के नित नए तरीके ईजाद कर रही है। और यह काम इतनी चालाकी से किया जा रहा है कि जनता को लगता है कि सब उसके भले के लिए है। जहरीली हवा में सांस लेते और जहरीला पानी पीते हुए भी जनता जब प्रधानमंत्री को यह कहते सुनती है कि मौसम का मज़ा लीजिए, तो उसे लगता है कि सांसें गिरवी रख देना ही राष्ट्रधर्म है। चीन के बाद नेपाल भी भारत के इलाकों पर अपना कब्जा दिखा चुका है, लेकिन जब मोदी कहते हैं कि ये नया भारत है, जो झुकता नहीं है, तो जनता गलवान से लेकर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर तक सब भूल जाती है। विपक्षी दलों पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए मोदी जब खुद बीजेपी और सहयोगी दलों में बेटे–बेटियों और रिश्तेदारों को आगे बढ़ाते हैं तो जनता को यह राजनैतिक चातुर्य लगता है। ऐसे दर्जनों उदाहरण पेश किए जा सकते हैं, जिसमें मोदी की कथनी और करनी में जमीन–आसमान जैसा अंतर दिखाई देता है। लेकिन जनता फिर भी भ्रमित हो चुकी है, क्योंकि मोदी के प्रचार तंत्र ने जमीन–आसमान के अंतर को उस क्षितिज की तरह पेश किया है, जहां जमीन–आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं।

रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटकते मृग की तरह जनता की हालत हो चुकी है। यह सब प्रचारतंत्र की बाजीगरी है। बहुत पहले जब देश में शुद्ध देसी घी ही खाया जाता था, तब वनस्पति घी बेचने के लिए बाजारों में मु त के पकवान परोसे जाते थे। बेचने और ठगने का यही तरीका अब राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसमें जनता केवल ठगा नहीं रही है, बल्कि राजनीति के चौपड़ में लोकतंत्र को दांव पर लगा रही है। कुरुसभा की तरह संवैधानिक संस्थाएं आंख पर पट्टी बांधे या देखे को अनदेखा कर जुए के इस तमाशे का मजा ले रही हैं।

इस जुए में अब मोदी सरकार ने लोगों के मोबाइल सेट के जरिए जासूसी का पांसा फेंका है। वो भी बेहद लुभावने नाम के साथ। संचार साथी ऐप, नाम से लगेगा हमारा कोई साथी है, यानी सुख–दुख में साथ देने वाला। लेकिन ये साथी तो असल में आस्तीन का सांप बनेगा, जो कब डसेगा कहा नहीं जा सकता। सबसे अच्छा स्मार्टफ़ोन सरकार ने पिछले सप्ताह मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को निर्देश दिया है कि भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए या आयात किए गए सभी नए मोबाइल हैंडसेट में 90 दिनों के भीतर संचार साथी ऐप प्री–इंस्टॉल हो जाए। दूरसंचार विभाग के निर्देश में अनिवार्य किया गया है कि भारत में इस्तेमाल के लिए लक्षित मोबाइल हैंडसेट के सभी निर्माताओं और आयातकों को जारी होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर विभाग को अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसमें आगे चेतावनी दी गई है कि अनुपालन में विफल रहने पर दूरसंचार अधिनियम, 2023, दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम, 2024, और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और विभाग द्वारा संशोधित या वापस लिए जाने तक लागू रहेगा।

इस आदेश के मुताबिक स्मार्टफ़ोन निर्माताओं को मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप को प्री–इंस्टॉल करना होगा। साथ ही पुराने फ़ोनों में इसे सॉ .टवेयर अपडेट के ज़रिए भेजा जाएगा। यानी जब आप अपने स्मार्ट फोन का सॉ टवेयर अपडेट करेंगे तो यह ऐप अपने आप फोन पर आ जाएगा। यह पहली बार है जब देश में किसी ऐप को इस तरह से हर डिवाइस में स्थायी रूप से रहने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस कदम का व्यापक विरोध शुरु हुआ और इसे बिग बॉस की तरह लोगों के निजी जीवन में तांक–झांक करने वाला करार दिया गया तो सरकार ने दावा किया कि ऐसा साइबर सुरक्षा के मद्देनजर किया जा रहा है ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि जिस तरह सरकार ने इजरायली सॉ टवेयर पेगासस के जरिए चोरी–छिपे जासूसी कराई थी, वही जासूसी अब ऐलान के साथ करने का दुस्साहस सरकार ने दिखाया है। इसे सीधे–सीधे तानाशाही करार दिया जा रहा है। हमेशा की तरह सरकार ने इस बार भी इसमें किसी से सलाह–मशविरा जरूरी नहीं समझा। बस एक आदेश जारी कर दिया।

जब विरोध के सुर तेज हुए तो दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक वैकल्पिक मोबाइल एप्लिकेशन बताते हुए कहा कि उपयोगकर्ता इसे अपने फोन से हटाने के लिए स्वतंत्र हैं। सिंधिया ने कहा अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो रजिस्टर मत करो और डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। लेकिन देश में हर व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये ऐप फ्रॉड से बचाने, चोरी से बचाने के लिए है। हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी ज़ि मेदारी है।

अब सिंधिया जी को कौन याद दिलाए कि जि मेदारियां तो आपकी सरकार पर और भी ढेर सारी हैं, पहले उन्हें पूरा कर लें। और जैसे हर व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये ऐप फ्रॉड से बचा सकता है, उसी तरह हर व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये ऐप हटाया भी जा सकता है। वैसे भी सिंधिया की बात को उनके ही मंत्रालय का दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 नकारता है। इस नियम के तहत दिए गए निर्देश का खंड 7(बी) कहता है–सुनिश्चित करें कि प्री–इंस्टॉल किया गया संचार साथी एप्लिकेशन पहले इस्तेमाल या डिवाइस सेटअप के समय अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से दिखे और सुलभ हो। इसकी कार्यक्षमताओं को अक्षम या प्रतिबंधित न किया जाए। इस निर्देश से साफ है कि मंत्रालय ने ऐप को हटाने पर रोक लगाई है। तो लोग मंत्रालय के निर्देश मानें या मंत्री की मुंहजुबानी बात पर यकीन करें। डिजिटल अधिकार वकालत संगठन, इंटरनेट फ्रीडम फ़ाउंडेशन (आईएफएफ) ने सिंधिया की टिप्पणियों का खंडन करते हुए कहा है कि स्पष्टीकरण गलत है% और आधिकारिक निर्देश स्पष्ट रूप से कहता है कि संचार साथी को %अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है%। आईएफएफ ने यह भी कहा है कि पर्सनल डिजिटल डिवाइस पर सरकारी कंट्रोल का तेज़ी से बढ़ना बहुत चिंता की बात है। ऐसे फैसले कानूनी तौर पर कमज़ोर हैं, और यूज़र की निजता के लिए खतरनाक है। सरकार का यह आदेश संविधान के भी खिलाफ है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार डिजिटल और टेलिकॉम से जुड़े फ़ैसले केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन साइबर अपराध को रोकना राज्यों की ज़ि मेदारी है। जब केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार अलग–अलग हैं, तो कोई नया नियम बनाने से पहले राज्यों और आम लोगों से सलाह–मशविरा क्यों नहीं किया गया? यह एक बड़ा सवाल है। बता दें कि भारत में डेटा प्रोटेक्शन क़ानून 2023 में साफ़ लिखा है कि किसी भी तरह का व्यक्तिगत डेटा लेने के लिए सहमति ज़रूरी है। लेकिन यहां तो सरकार बिना यूज़र की मर्जी के उसके फोन में घुसने की कोशिश कर रही है। फोन में क्या रहेगा और क्या नहीं, यह तय करने का अधिकार हमारी निजी स्वतंत्रता का हिस्सा है। ऐसे में, अगर संचार साथी ऐप को फोन से हटाने का विकल्प नहीं मिलेगा तो यह यूज़र की निजता, स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ माना जा सकता है। सबसे अच्छा स्मार्टफ़ोन

यह बताने की जरूरत नहीं कि मोबाइल फ़ोन सबकी पर्सनल स्पेस होती है। एक घर के सदस्य ही एक–दूसरे से अपने मोबाइल फोन के पासवर्ड साझा नहीं करते हैं। भले कुछ छिपाने को न हो, फिर भी एक–दूसरे के फोन पर झांकना बदतमीजी समझा जाता है। क्योंकि यहां निजी बातें होती हैं, कई जरूरी नोट्स संभाल कर रखे जाते हैं। यादगार तस्वीरें होती हैं। जैसे पहले लोग डायरी लिखते थे और किसी की डायरी पढ़ना खराब आदत मानी जाती थी, वही व्यवहार अब मोबाइल के साथ हो चुका है। ऐसे में संचार साथी ऐप मोबाइल में होने के बाद खतरा बना रहेगा कि यह ऐप हमारे फ़ोन की फ़ाइलें, फ़ोटो या मैसेज देख लेगा या भविष्य के किसी अपडेट में ऐसा कर सकता है। अभी भले ही सरकार इसे डिजिटल सुरक्षा का औजार बता रही है, लेकिन असल में इसी औजार से सबसे ज्यादा सेंध लगने का खतरा रहेगा, ऐसा जानकार मान रहे हैं। संचार साथी ऐप से अनेक प्रकार का डेटा सरकार के पास आएगा और आज की तकनीकी क्षमता वाली पूंजीवादी राजनीति में डेटा ही सबसे बड़ी संपत्ति किसी देश के लिए बन चुका है।

विविध समाचार

पंजाब में कांग्रेस नेता के बेटे ने की आत्महत्या, मरने से पहले बनाया वीडियो, बिल्डर पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप

बठिंडा। पंजाब के बठिंडा जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। मौड़ मंडी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके दिवंगत कांग्रेसी नेता सुखराज नत्त के बेटे एडवोकेट दविंदर नत्त ने रविवार देर रात अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने से पहले दविंदर नत्त ने 8 मिनट 45 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार चंडीगढ़ के एक नामी बिल्डर को ठहराया है। दविंदर ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने उनके साथ 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पैसे वापस पाने के लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी से भी बिल्डर को फोन करवाया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वीडियो के अंत में उन्होंने भावुक होते हुए अपने परिवार के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। दविंदर नत्त पेशे से वकील थे। उनके पिता सुखराज नत्त का पहले ही निधन हो चुका है और घर में वह अपनी वृद्ध मां के साथ रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल शव को अस्पताल में रखा गया है, जहां रिश्तेदारों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बठिंडा के SP सिटी नरिंदर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि "मृतक ने मरने से पहले 'सुषमा बिल्डर्स' के मालिक और उनके बेटों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने वीडियो को साक्ष्य के रूप में कब्जे में ले लिया है। मृतक की मां के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।"

160 करोड़ रुपए गबन मामला : पंचकूला–पानीपत में कोटक महिंद्रा–एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाहर पुलिस तैनात, शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं

पंचकूला। हरियाणा में कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े लगभग ध्160 करोड़ के कथित गबन मामले में सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। पंचकूला और पानीपत में बैंक शाखाओं के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। सोमवार सुबह बैंक कर्मचारियों को शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं दी गई और स्टाफ बाहर ही खड़ा रहा। बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो को दोनों बैंकों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। मामला पंचकूला नगर निगम द्वारा कराए गए फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ा है। नगर निगम ने विभिन्न बैंकों में करीब 160 करोड़ की एफडी करवाई थी। इनमें से कुछ एफडी के मैच्योर होने पर उनके रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां सामने आईं। जांच के अनुसार, नगर निगम ने कोटक महिंद्रा बैंक में कुल 16 एफडी करवाई थीं। इनमें से 11 एफडी, जिनकी कुल राशि ध्59.58 करोड़ थी, 16 फरवरी 2026 को मैच्योर हो गईं। लेकिन मैच्योरिटी के बाद बैंक द्वारा दिए गए विवरण नगर निगम के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। खाता संख्या 2046903758 के संबंध में 16 मार्च 2026 को प्राप्त बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, 13 मार्च को खाते में अपेक्षित 50.07 करोड़ की जगह केवल 2.18 करोड़ शेष थे।

वहीं, बैंक ने यह भी बताया कि कोई सक्रिय एफडी मौजूद नहीं है और 18 मार्च 2026 तक खातों में कुल शेष राशि 12.86 करोड़ ही रह गई थी। प्रारंभिक जांच में एफडी से जुड़े लेनदेन और रिकॉर्ड में बड़ी अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है।

पंजाब सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की दी मंजूरी, इस महीने से सीधे बैंक खातों में आएंगे पैसे

चंडीगढ। पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने की योजना पर अंतिम मुहर लगा दी गई। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति ँ(ब) वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगे। सरकार ने तय किया है कि यह राशि अप्रैल से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति दी गई। इससे पहले 8 मार्च को पेश किए गए बजट में 'मुख्यमंत्री मावां–धीयां सत्कार योजना' का ऐलान किया गया था, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया गया था। करीब 9,300 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट वाली इस योजना से राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जानकारी दी है कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 13 अप्रैल, यानी बैसाखी के दिन से शुरू की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ–साथ उनके सामाजिक सशक्तिकरण में भी अहम भूमिका निभाएगी।

अनियंत्रित होकर खड्ड में गिरी कार, जेबीटी शिक्षक और युवती की मौत, तीन घायल

शाहपुर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंतर्गत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार रात को सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चडी–घेरा मार्ग पर हनुमान मंदिर के समीप एक कार अनियंत्रित होकर नीचे खड्ड के किनारे जा पहुंची। हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी के सभी पार्ट अलग होकर बिखर गए। इस दर्दनाक हादसे में एक जेबीटी शिक्षक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी लोग शुक्रवार रात को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में हनुमान मंदिर के पास चालक ने अचानक कार से नियंत्रण खो दिया। इससे कार सड़क से नीचे खड्ड में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों और घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकाला। मृतकों की पहचान करण बहादुर(40) पुत्र वीर बहादुर और करीना देवी(18) पुत्री सुरेश कुमार के रूप में हुई है। दोनों मृतक ग्राम पंचायत भितलू के गांव कुट के निवासी थे। करण बहादुर राजकीय प्राथमिक पाठशाला कल्याडा में बतौर जेबीटी शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे थे। हादसे में घायल तीन अन्य व्यक्तियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद तुरंत जोनल अस्पताल धर्मशाला रेफर दिया गया है, जहां वे उपचाराधीन हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के असल कारणों की जांच शुरू कर दी है।

सम्राट अशोक की भारतीय इतिहास में महता

भारतीय इतिहास के फलक पर सम्राट अशोक एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हैं, जिनका प्रभाव केवल सीमाओं को जीतने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने मानवीय हृदय को जीतने का मार्ग प्रशस्त किया। मौर्य वंश के तीसरे शासक के रूप में अशोक का महत्व केवल एकचक्रवर्ती सम्राटहोने में नहीं, बल्कि एक धम्म–विजयीसुधारक के रूप में है।अशोक का सबसे बड़ा महत्व उनके हृदय परिवर्तन में निहित है। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात ने उन्हें विजय की पारंपरिक परिभाषा बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने भेरीघोष अर्थात युद्ध का नाद को त्यागकर धम्मघोष अर्थात नैतिकता का नाद को अपनाया। इतिहास में यह विरल उदाहरण है, जहां एक विजेता ने अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर हिंसा का परित्याग कर दिया हो।अशोक ने धम्मके रूप में एक साझा नैतिक संहिता प्रस्तुत की। यह कोई संकुचित धर्म नहीं था, बल्कि माता–पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, जीव दया और सहिष्णुता जैसे मानवीय मूल्यों का मिश्रण था। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में उन्होंने भाषाई और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया।अशोक ने राजत्व के सिद्धांत को एक नया आयाम दिया। उन्होंने उद्घोषणा की– सबे मुनिसे पजा ममा अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, कुएं खुदवाना, और मनुष्यों के साथ–साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनवाना उनकी दूरगामी सोच को दर्शाता है। वे जनकल्याणकारी राज्य का मॉडल अर्थात आधुनिक वेलफेयर स्टेटके प्राचीन प्रणेता थे।भारतीय कला को पत्थरों के माध्यम से अमर बनाने का श्रेय अशोक को ही जाता है। उनके द्वारा स्थापित एकाश्म स्तंभ अर्थात मोनोलिथिक पिल्लर्स और शिलालेख न केवल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, बल्कि वे इतिहास लेखन के जीवंत स्रोत भी हैं। सारनाथ का सिंह शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय चिह्न है और उनके धम्म चक्र को तिरंगे में स्थान मिलना उनकी प्रासंगिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है।अशोक के बिना बौद्ध धर्म शायद एक क्षेत्रीय संप्रदाय बनकर रह जाता। उन्होंने इसे विश्व धर्म बनाने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को विदेशों में भेजा। उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सॉफ्ट पावरके जरिए भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को मध्य एशिया सेलेकर दक्षिण–पूर्व एशिया तक फैलाया। अशोक की महत्ता इस बात में है कि उन्होंने शासन को धर्म अर्थात नैतिकता से जोड़ा। उन्होंने सिद्ध किया कि वास्तविक महानता साम्राज्य के विस्तार में नहीं, बल्कि प्रजा के चरित्र उत्थान में है। वे आज भी भारतीय चेतना के ऐसे प्रतीक हैं जो शक्ति और करुणा के संतुलन की प्रेरणा देते हैं।लेकिन यह एक विडंबना ही है कि जिस सम्राट ने भारत को एक सूत्र में पिरोया, वह सदियों तक भारतीय विमर्श और इतिहास की मुख्यधारा से ओझल रहा। 19वीं सदी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा उनके शिलालेखों को पढ़े जाने से पहलेअशोक का नाम केवल पुरानी कथाओं तक सीमित था।उनकी इस ऐतिहासिक उपेक्षाके अनेक कारण रहे हैं।अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देने और पशु बलि पर रोक लगाने से तत्कालीन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हितों को चोट पहुंची थी। इसी कारणपुराण आदिधर्मग्रंथों में मौर्य वंश का वर्णन तो मिलता है, लेकिन अशोक को वह महानता अथवा विस्तार नहीं दिया गया, जो उनके कद के अनुरूप था। उन्हें अक्सर केवल एक शासक के रूप में दर्ज किया गया, न कि एक महान सुधारक के रूप में।मध्यकाल तक आते–आते भारत से बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। चूंकि अशोक की अधिकांश कीर्ति और उनके शिलालेख बौद्ध केंद्रों और पाली, प्राकृत भाषा से जुड़े थे, इसलिए बौद्ध धर्म के विलोपन के साथ अशोक की गाथाएं भी लोकस्मृति से धुंधली पड़ती गईं।अशोक ने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखवाए थे। समय के साथ इन लिपियों को पढ़ने वाले लोग नहीं रहे। लोग इन स्तंभों को देखते तो थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि ये किस देवानांपिय दसी अर्थात देवताओं के प्रिय राजा के हैं। इसे जानने के उद्देश्य से फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें दिल्ली मंगवाया था। मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखकों, दरबारी इतिहासकारों का ध्यान मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य पर रहा। उनके लिए प्राचीन भारत के अहिंसकऔर धम्मआधारित शासन का कोई विशेष राजनीतिक महत्व नहीं था।भारतीय इतिहास में महानताको अक्सर युद्धों और विजय अभियानों से मापा गया, जैसे समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में युद्ध त्याग दिया था, जिसे कुछ इतिहासकारों ने साम्राज्य के पतन का कारण मानकर उनकी सैन्य अक्षमता के रूप में व्याख्यायित किया, जिससे उनकी छवि एक मजबूत राजाके बजाय एक भिक्षु राजाकी बन गई।अशोक की वास्तविक पहचान आधुनिक काल में तब लौटी जब औपनिवेशिक काल के पुरातत्वविदों ने उनके शिलालेखों को डिकोड किया। आज वे भारतीय गणतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक चिह्न– अशोक चक्र और सिंह शीर्ष के रूप में विराजमान हैं। लेकिन दुखद यह है कि अब तक देश में राजकीय अथवा राष्ट्रीय समरोह के रूप में सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाई जाती और न ही उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश ही घोषित की गई है।सम्राट अशोक की जयंती को लेकर उपेक्षा का कारणउसके पीछे ऐतिहासिक अस्पष्टता और आधुनिक राजनीतिक प्राथमिकताएं प्रमुख हैं। सम्राट अशोक के जन्म की कोई सटीक प्रमाणिक तिथि इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। बौद्ध ग्रंथों और शिलालेखों में उनके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन तो है, लेकिन उनकी जन्म तिथि को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। बिना किसी सर्वसम्मत तिथि के सरकारी स्तर पर जयंतीघोषित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। आधुनिक काल में सम्राट अशोक का इतिहास 1837 में ब्राह्मी लिपि पढ़े जाने के बाद मुख्यधारा में आया। तब तक भारत में शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप आदि कई अन्य महापुरुषों की लोक–स्मृतियां और तिथियां स्थापित हो चुकी थीं। अशोक की महानता को इतिहासकी किताबों में तो जगह मिली, लेकिन वे लोकसंस्कृति में उस तरह उत्सव का हिस्सा नहीं बन पाए।किसी भी महापुरुष की जयंती और अवकाश अक्सर सामाजिक आंदोलनों या राजनीतिक दबाव का परिणाम होते हैं। लंबे समय तक अशोक को केवल एक प्राचीन राजाके रूप में देखा गया। हालांकिहाल के वर्षों में बिहार आदि कुछ राज्यों में चौत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक जयंती मनाने की शुरुआत हुई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह सर्वमान्य नहीं हो पाया है।स्वतंत्र भारत की सरकार ने अशोक को व्यक्तिगत रूप से पूजने के बजाय अशोक चक्र और सिंह शीर्ष आदि उनके प्रतीकों को राष्ट्र का आधार बनाया। ऐसा माना गया कि उनके आदर्श संविधान और राष्ट्रीय ध्वज में समाहित हैं, इसलिए अलग से व्यक्ति पूजाया अवकाश पर ध्यान कम रहा।वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने के लिए नए सार्वजनिक अवकाशों को घोषित करने से बचती हैं। पहले से ही महापुरुषों की लंबी सूची होने के कारण नई छुट्टियों को जोड़ने में प्रशासनिक बाधाएं आती हैं।हाल के दशकों में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की मांग के बाद बिहार सरकार ने सम्राट अशोक जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसे लेकर मांग और आयोजन बढ़े हैं। सम्राट अशोक सिर्फ नाम नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के वह गौरवशाली पृष्ठ हैं, जिसके कारण भारत की पहचान होती है, गौरवशाली इतिहास के उनके विरासत के चिह्न ही भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों में विराजमान है।ऐसे में उनके जन्मोत्सव पर सरकार को सोचना ही चाहिए।सम्राट अशोक की जन्म तिथि को लेकर इतिहासकारों और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में गहरी अस्पष्टता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में उनकी जयंती को लेकर मुख्य रूप से तीन मान्यताएं प्रचलित हैं।

इनके जन्म के संबंध में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से मानी जाने वाली भारतीय पंचांग की तिथि चौत्र शुक्ल अष्टमी है, जिसे अशोकाष्टमी के रूप में मनाया जाता है।कई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों का तर्क है कि इसी दिन सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। वर्ष 2026 में यह तिथि 26 मार्च को थी।इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है और अशोक व्रतरखा जाता है, जिसे लोकपरंपरा में सम्राट अशोक की स्मृति से जोड़कर देखा जाता है। वर्ष 2015 में बिहार सरकार ने घोषणा की कि सम्राट अशोक की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी।बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई 14 अप्रैल की तिथि ऐतिहासिक शोध के बजाय प्रशासनिक और सामाजिक समन्वय का परिणाम अधिक मानी जाती है।इतिहासकारों का मानना है कि इस तिथि का कोई ठोस प्राचीन ऐतिहासिक आधार नहीं है। आलोचकों के अनुसारइसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती के साथ जोड़कर एकराजनीतिक और सामाजिक संतुलन बनाने के उद्देश्य से चुना गया था। इतिहासकारों ने उनके शासनकाल और शिलालेखों के आधार पर उनके जन्म के वर्ष का अनुमान लगाया है।अधिकांश विद्वानों के अनुसार अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व के आस–पास पाटलिपुत्र में हुआ था।यह गणना उनके राज्याभिषेक (लगभग 268– 269 ईसा पूर्व) और उनके शिलालेखों में वर्णित समकालीन यूनानी राजाओं के समय के आधार पर की गई है।दिव्यावदान और अशोकावदान जैसे ग्रंथों में अशोक के जीवन की कथाएं तो हैं, लेकिन वे विशिष्ट तिथियों के बजाय बुद्ध के महापरिनिर्वाण के सौ– दो सौ साल बाद की घटनाओं पर केंद्रित हैं।अशोक के अपने शिलालेखों में उनके धम्म और शासन के वर्षों का उल्लेख है,लेकिन उनके जन्म दिवस के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं मिलती। लोक–कथाओं के अनुसारकलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात के बाद जब अशोक ने शस्त्र त्याग दिए और बुद्ध की शरण ली, तो उन्होंने इसी दिन शांति और करुणा का संकल्प लिया था। इसीलिए इसे उनके पुनर्जन्मया धम्म जन्मके रूप में देखा जाता है।अशोक ने अपने शासन में जीव हत्या और बलि पर रोक लगाई थी। अशोकाष्टमी के दिन सात्विक पूजा और जीव दया पर जोर देना उनके इसी अहिंसक शासन की याद दिलाता है।उड़ीसा के भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज की भव्य रथयात्रा इसी दिन (अशोकाष्टमी) निकलती है। कलिंग (उड़ीसा) वह भूमि थी, जिसने अशोक को बदला था।

वहां इस तिथि का इतना महत्व होना यह दर्शाता है कि अशोक का प्रभाव धार्मिक उत्सवों में रच–बस गया है।यद्यपि यह पर्व सदियों से मनाया जा रहा था, लेकिन इसे सम्राट अशोक जयंतीके रूप में औपचारिक पहचान हाल के वर्षों में मिली है। सामाजिक आंदोलनों ने अशोकाष्टमीको अशोक जयंतीके रूप में प्रचारित किया ताकि एक ऐतिहासिक महापुरुष को धार्मिक तिथियों के माध्यम से समाज में पुनः स्थापित किया जा सके।अशोकाष्टमी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि यह सम्राट अशोक द्वारा फैलाए गए शोकरहितअर्थात अ–शोक समाज के निर्माण के संकल्प का वार्षिक स्मरण उत्सव है।

–अशोक "प्रवृद्ध"

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, शनिवार 08 अगस्त 2026 | पृष्ठ-6

गृहिणियों से उद्यमियों तक: राउरकेला इस्पात संयंत्र की सीएसआर पहल बुन रही है सतत आजीविका की प्रेरक कहानियाँ

राउरकेला ०७/०८ (संवाददाता): जालडा पुनर्वास कॉलोनी की निवासी सुश्री तुलसी कुश गर्व के साथ कहती हैं इस केंद्र ने न केवल मेरे कौशल को निखारा है, बल्कि मेरे आत्मविश्वास और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदल दिया है, । मई 2025 में उन्होंने राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रशिक्षु के रूप में इस पहल से जुड़कर अपनी यात्रा शुरू की थी और आज वे स्वयं एक प्रशिक्षिका के रूप में अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। वे बताती हैं, जब मैंने आरएसपी द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लिया था, तब मेरी केवल इतनी ही इच्छा थी कि सिलाई सीखकर परिवार की आय में थोड़ा योगदान दे सकूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं एमएसएमई के तहत पंजीकृत एक उद्यम का हिस्सा बनूँगी, जिससे सरकारी सुविधाओं और नए अवसरों तक पहुँच संभव होगी।卐

जालडा पुनर्वास कॉलोनी की महिलाओं के लिए शुरू किया गया एक साधारण सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आज एक सफल महिला-नेतृत्व वाले प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र (टीसीपीसी) के रूप में विकसित हो चुका है। सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के मार्गदर्शन और संरक्षण में यह पहल महिलाओं को सतत आजीविका के अवसर प्रदान करते हुए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रही है।टीसीपीसी की यात्रा 28 मई 2025 को शुरू हुई, जब जालडा पुनर्वास कॉलोनी की 15 महिलाओं ने आरएसपी के पार्श्वांचल विकास संस्था में प्रशिक्षण के प्रथम चरण में भाग लिया। आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा संचालित इस पहल में ग्राम उत्थान के परियोजना प्रबंधक, श्री गुरूचरण महंती ने प्रतिभागियों की पहचान और उन्हें जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशिक्षण उषा सिलाई द्वारा प्रदान किया गया, जिन्होंने महिलाओं को सिलाई के बुनियादी एवं उन्नत कौशलों से लैस किया।प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने प्रारंभ में बुनियादी सिलाई तकनीकें सीखीं और बाद में महिलाओं एवं पुरुषों की शर्ट-पैंट, ज़्लाउज, पेटीकोट, कुर्ती, सलवार-सूट, कपड़े के बैग, एप्रन, जैकेट और स्कर्ट सहित विभिन्न परिधानों एवं उपयोगी वस्तुओं को बनाना सीखा। कढ़ाई, एप्लीक के काम तथा कटवर्क जैसे विशेष प्रशिक्षणों ने उनके उत्पादों की गुणवज़ा और बाजार क्षमता को और बढ़ाया। कार्यक्रम की निरंतरता सुनिश्चित करने और स्थानीय उत्पादन केंद्र विकसित करने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जालदा में प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र विकसित किया गया। जुलाई 2025 में आयोजित दूसरे चरण तथा अज़्टूबर 2025 में आयोजित तीसरे चरण के प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने आंगनवाड़ी बच्चों की वर्दियों सहित विभिन्न उत्पादन ऑर्डर लेना शुरू किया। बाद के प्रशिक्षण चरणों में उन्हें क्विल्टिंग, पैचवर्क, साड़ियों पर फ्रेम वर्क, नेट वर्क, वॉल हैंगिंग, पर्दे तथा गृह सज्जा उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। समूह के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाले आंगनवाड़ी बच्चों की वर्दियों की सिलाई के पहले ऑर्डर को याद करते हुए तुलसी कहती हैं कि, 卐इससे हमें विश्वास मिला कि हम गुणवज़ापूर्ण कार्य कर सकते हैं और बाजार की प्रतिस्पर्धा के साथ बने रह सकते हैं। आज हम स्वयं को केवल प्रशिक्षु नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए योगदान देने वाली उद्यमी के रूप में देखते हैं卐 ।समय के साथ इस केंद्र ने अपनी क्षमताओं और ग्राहक आधार का लगातार विस्तार करते हुए अंतत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त कर लिया है । इस उपलज़्धि ने समूह को सरकारी सहायता योजनाओं तक पहुँच, नए व्यावसायिक अवसरों की खोज तथा एक सतत सामुदायिक उद्यम के रूप में अपनी पहचान को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान की है।

समूह की कई सदस्य अब अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही हैं, जिससे कौशल विकास और उद्यमिता का लाभ आसपास के क्षेत्रों तक पहुँच रहा है तथा इसका सकारात्मक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसी पहलों के माध्यम से आरएसपी केवल व्यावसायिक कौशल प्रदान नहीं कर रहा, बल्कि महिलाओं को सज़्मानजनक आजीविका अर्जित करने, आत्मविश्वास विकसित करने और स्थानीय आर्थिक विकास की सक्रिय भागीदार बनने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। आज जालडा में सिलाई मशीनों की आवाज केवल कपड़े नहीं सिल रही है, बल्कि आकांक्षा, संघर्ष, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की नई कहानियाँ भी बुन रही है। तुलसी कुश और उनकी साथी महिलाओं के लिए टीसीपीसी एक उज्ज्वल भविष्य का द्वार बन चुका है, जो यह सिद्ध करता है कि जब अवसर और संकल्प का संगम होता है, तब सतत परिवर्तन अवश्य संभव होता है।टीसीपीसी मॉडल कौशल विकास, बाजार संपर्क, संस्थागत सहयोग और उद्यमिता संवर्धन के माध्यम से समावेशी विकास के प्रति सेल-आरएसपी की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

बालासोर बीच पर 50 क्विंटल से ज़्यादा वज़न वाली बड़ी व्हेल शार्क की लाश मिली

बालासोर ०७/०८ (संवाददाता): बालासोर के भोगराई समुद्र तट क्षेत्र में तलासरी में 30 फीट से अधिक लंबाई वाली एक विशाल व्हेल शार्क का शव मिला। मछली का वजन 50 क्विंटल से अधिक होने का अनुमान है, यह इस क्षेत्र में देखी जाने वाली अपने आकार की पहली मछली है, जिसने निवासियों और आगंतुकों दोनों का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्टों के अनुसार, भोगराई में सहबाजीपुर के पांच मछुआरे बुधवार सुबह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। उन्होंने किनारे से लगभग 700 फीट दूर अपना जाल डाला, और इसे खींचने की प्रक्रिया के दौरान व्हेल शार्क अन्य मछलियों के साथ उलझ गई। जब तक इसे करीब लाया गया, तब तक मछली मर चुकी थी। मछुआरों ने पहले व्हेल शार्क को मैन्युअल रूप से किनारे पर खींचने का प्रयास किया, लेकिन इसके आकार और वजन के कारण ऐसा करने में असमर्थ रहे।

लेकिन, जब मछली किनारे से करीब 50 फीट दूर पहुँची, तो कम गहरे पानी की वजह से उसे और आगे खींचना नामुमकिन हो गया। मछुआरों और आस-पास के लोगों समेत करीब 100 लोगों ने मछली को बीच पर खींचने की कोशिश की, लेकिन बार-बार कोशिश करने के बाद भी कोशिश कामयाब नहीं हुई।

तब से इस बड़ी व्हेल शार्क की मौजूदगी ने टूरिस्ट और आस-पास के लोगों की बड़ी भीड़ को अपनी ओर खींचा, और कई लोग इस अनोखी चीज़ की एक झलक पाने के लिए उस जगह पर आए।

इन्वेंशन का कमाल, आदिवासी युवक ने लगाया 5 रुपये का बाइक वॉश

ज़्योंझर ०७/०८ (संवाददाता): इनोवेशन और कज़्युनिटी-ओरिएंटेड सोच का एक शानदार उदाहरण, ज़्योंझर के हरिचंदनपुर ज़्लॉक के ब्राहमणीपाल का एक आदिवासी युवक, सिर्फ़ 5 रुपये में पूरी बाइक साफ़ करने वाली एक ऑटोमेटेड बाइक-वॉश मशीन लगाकर इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। इस अनोखी पहल ने लोगों का बहुत ध्यान खींचा है, और बाइक मालिकों की लंबी लाइनें इस बहुत सस्ती सर्विस को आज़माने के लिए लग गई हैं। रसोल पंचायत के तहत व्यस्त ब्राह्मणीपाल बाज़ार के सड़क किनारे लगी यह मशीन सिर्फ़ 10 मिनट में एक टू-व्हीलर धो देती है।

यूज़र सिस्टम में रुपये 5 का सिक्का डालते हैं, जो गाड़ी को साफ़ करने के लिए तेज़ रज़्तार वाला पानी छोड़ने वाली एक प्रेशर गन को एज़्टिवेट करता है। ऐसे समय में जब रेगुलर बाइक-वॉश सेंटर रुपये 70 से रुपये 80 के बीच चार्ज करते हैं, यह कम लागत वाला विकल्प आदिवासी-बहुल इलाके में भीड़ खींचने वाला बन गया है। इस इनोवेशन के पीछे ब्राह्मणीपाल के एक युवा इन्वेंटर जितेंद्र हेज़्ब्रम हैं। यह उनका पहला टेज़्नोलॉजिकल एज़्सपेरिमेंट नहीं है। 2019 में, जितेंद्र को एक पेट्रोल ATM बनाने के बाद पहचान मिली, जिसमें 100 रुपये का नोट डालने पर यूल निकलता था। यह इन्वेंशन गाड़ी चलाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया ज़्योंकि ज़्योंझर-जाजपुर बॉर्डर पर 20 किलोमीटर के दायरे में कोई पेट्रोल पंप नहीं था।

एक आम बैकग्राउंड से आने वाले जितेंद्र, कहनू चरण हेज़्ब्रम और डुमुनी हेज़्ब्रम की तीसरी संतान हैं। पैसे की तंगी की वजह से उन्हें मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अपने परिवार का गुज़ारा करने के लिए, उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में इलेज़्ट्रिकल वायरिंग का काम शुरू किया, लेकिन इनोवेशन में उनकी दिलचस्पी उनके स्कूल के दिनों से है, जहाँ उन्होंने साइंस एग्ज़िबिशन में हिस्सा लिया था। अपने सफ़र के बारे में बात करते हुए, जितेंद्र ने कहा कि उन्हें उज़्मीद है कि अगर उन्हें पैसे की मदद मिली तो वे इनोवेशन करते रहेंगे। उनका सपना एक कम लागत वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है जो लोगों को सस्ते में सफ़र करने में मदद कर सके।

मैंने सबसे पहले एक मिनी-पेट्रोल पंप बनाया। मैंने इस पर आठ महीने लगाए और धीरे-धीरे इससे बहुत कुछ सीखा। बाइक-वॉश ञ्चरू का आइडिया भी मुझे तभी आया था। ज़्योंकि यह एक आसान चीज़ थी, इसलिए मैंने इसे तब नहीं बनाया था, खुश जितेंद्र ने कहा। हमारा इलाका माइनिंग एरिया है। यहाँ बाइक सर्विसिंग की कोई सुविधा नहीं है।

राज्यव्यापी अभियान में अवैध गांजा खेती पर कार्रवाई

भुवनेश्वर ०७/०८ (संवाददाता):ओडिशा पुलिस ने गैर-कानूनी भांग की खेती के खिलाफ पूरे राज्य में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। स्पेशल टास्क टीम, ड्रोन, सैटेलाइट और इंटेलिजेंस पर आधारित निगरानी का इस्तेमाल करके मिलकर किए गए ऑपरेशन के ज़रिए कई जिलों में हज़ारों एकड़ गैर-कानूनी खेती को खत्म कर दिया गया है। लोगों की भलाई और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के मकसद से, प्रभावित जिलों में पुलिस यूनिट्स ने खास टीमें बनाई हैं जो खासकर दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में गैर-कानूनी भांग के खेतों का पता लगाकर उन्हें खत्म करना जारी रखती हैं। यह चल रही कोशिश राज्य के इतिहास के सबसे बड़े एंटी-नारकोटिज़्स कैंपेन में से एक है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, 2025 तक 18,111 एकड़ से ज़्यादा भांग की खेती पहले ही खत्म कर दी गई है, और यह कैंपेन मार्च 2026 तक जारी रहने वाला है।

इस साल नवंबर के आखिर तक, पूरे ओडिशा में मारिजुआना तस्करी से जुड़े 473 मामले दर्ज किए गए थे। ओडिशा के डायरेज़्टर जनरल ऑफ पुलिस योगेश बहादुर खुरानिया ने इस तेज़ी से हो रही तरक्की की तारीफ करते हुए कहा कि इतने कम समय में बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी खेती को खत्म करना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले महीनों में भी यह कैंपेन इसी सज़्ती से जारी रहेगा। इसकी तुलना में, 2024 में 594 केस रजिस्टर हुए थे, और पूरे राज्य में 20,803 एकड़ से ज़्यादा भांग के बागान खत्म कर दिए गए थे। रायगढ़ा, मलकानगिरी, कोरापुट, बौध, कंधमाल, गजपति, गंजम और नबरंगपुर में गैर-कानूनी खेती की खबरें आ रही हैं। पुलिस छिपे हुए खेतों की पहचान करने और उन्हें खाली कराने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन सर्विलांस का इस्तेमाल कर रही है। ध्रक्क खुरानिया ने दोहराया कि मारिजुआना की खेती करने या प्रोडज़्शन में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सज़्त कार्रवाई की जाएगी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र सतत इस्पात निर्माण के माध्यम से हरित भविष्य का निर्माण

राउरकेला ०७/०८ (संवाददाता): जब विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है और एक सतत भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर रहा है, तब सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) यह निरंतर प्रदर्शित कर रहा है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आरएसपी ने देश के अग्रणी पर्यावरण-अनुकूल इस्पात उत्पादकों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिए लगातार नई तकनीकों, संसाधनों के संरक्षण के उपायों, कचरे के उपयोग की पद्धतियों और उत्सर्जन में कमी लाने की पहलों को अपनाया है।

पर्यावरणीय स्थिरता आरएसपी की कार्यप्रणाली का एक अभिन्न अंग है । ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और उत्सर्जन नियंत्रण के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों के माध्यम से संयंत्र ने अपने पर्यावरणीय प्रभाव को लगातार कम किया है, साथ ही उत्पादन स्तर में भी वृद्धि सुनिश्चित की है। जीवाश्म ईंधनों की खपत में कमी लाना संयंत्र के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा है। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, इस्पात निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट गैसों का प्रभावी उपयोग कैप्टिव पावर प्लांट-1 के बॉयलरों में किया जा रहा है, जिससे बॉयलर-ग्रेड कोयले की आवश्यकता में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे न केवल बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो रहा है, बल्कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता मिल रही है।

हरित इस्पात निर्माण की दिशा में एक और अग्रणी कदम उठाते हुए, आरएसपी ने ज़्लास्ट फर्नेस-1 में बायोचार इंजेज़्शन का परीक्षण प्रारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक कार्बन स्रोतों को आंशिक रूप से नवीकरणीय जैव-आधारित विकल्पों से प्रतिस्थापित करना है, जिससे लौह निर्माण प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। इस परीक्षण के परिणाम संयंत्र की अन्य ज़्लास्ट फर्नेसों में भी इस तकनीक को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

संसाधन दक्षता और चक्रित अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) के सिद्धांत भी आरएसपी की पर्यावरणीय रणनीति के केंद्र में हैं। संयंत्र ने धातुकर्मीय उप-उत्पादों के प्रभावी उपयोग में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। ज़्लास्ट फर्नेस स्लैग का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, जबकि बीओएफ और एसएमएस स्लैग की बड़ी मात्रा को बुनियादी ढांचा निर्माण तथा अन्य उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जा रहा है। इन प्रयासों से न केवल अपशिष्ट निपटान में कमी आई है, बल्कि औद्योगिक उप-उत्पादों से मूल्य सृजन भी हुआ है।

जल संरक्षण भी आरएसपी की एक बड़ी उपलज़्धि के रूप में उभरा है। जल प्रबंधन प्रणालियों में निरंतर सुधार, पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं और उत्पादन प्रक्रिया के अनुकूलन के माध्यम से संयंत्र ने अपनी विशिष्ट जल खपत में लगातार कमी लाई है। विज़ीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरएसपी ने प्रति टन कच्चे इस्पात (द्वश/ञ्च्ष्टस्र) पर 2.94 घन मीटर जल खपत का रिकॉर्ड बनाया, जो संयंत्र के इतिहास में अब तक का सबसे कम स्तर है। यह उपलज़्धि जिज़्मेदार जल प्रबंधन के प्रति संयंत्र के सतत प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हुए, आरएसपी शून्य तरल अपशिष्ट निर्वहन (द्दह्र्श स्द्भह्व-ह्वद्बस्र ष्ठद्बह्यष्ड्डद्धद्दद्ग - ‘स्ठ) के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पहल के तहत अतिरिक्त जल उपचार प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिससे उपचारित जल के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, ताजे जल की खपत कम होगी और अपशिष्ट जल का पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

संयंत्र ने अन्य प्रमुख स्थिरता संकेतकों में भी निरंतर सुधार दर्ज किया है, जिनमें विशिष्ट कार्बन डाइऑज़्साइड उत्सर्जन, कणीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) उत्सर्जन तथा जल खपत में कमी शामिल है। ये उपलज़्धियाँ स्वच्छ उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग के प्रति आरएसपी के केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, आरएसपी ने व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया है और अब तक अपने परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में 52 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। इससे जैव विविधता को बढ़ावा मिला है और वायु गुणवज़ा में सुधार हुआ है। राउरकेला इस्पात नगरी का हरित एवं स्वच्छ वातावरण, धरती माता के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत करता है।